₹ 10

www.kewalsachtimes.com

सितम्बर 2024

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIIBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

जानवरों की चर्बी को लेकर

सियासी घमासान

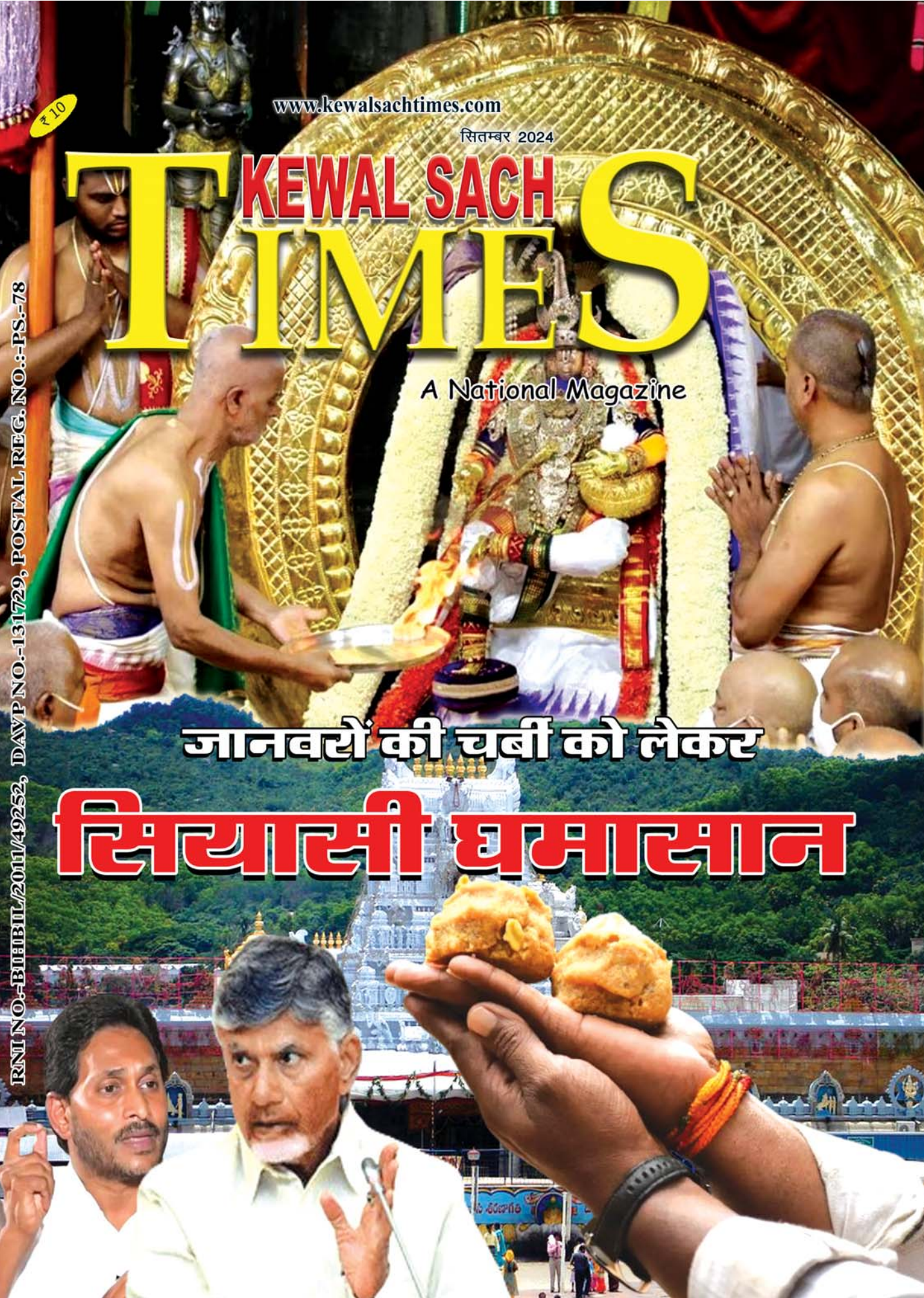

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

विवेक ओबेरॉय
03 सितम्बर 1976

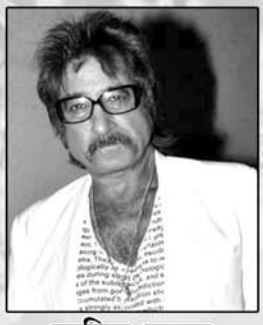

शक्ति कपूर
03 सितम्बर 1952

ऋषि कपूर
04 सितम्बर 1952

यशवंत सिन्हा
06 सितम्बर 1937

आशा भोसले
08 सितम्बर 1933

अक्षय कुमार
09 सितम्बर 1967

रामजेठ मलानी
10 सितम्बर 1923

महिमा चौधरी
13 सितम्बर 1973

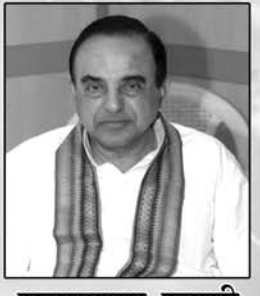

सुब्रमण्यम स्वामी
15 सितम्बर 1939

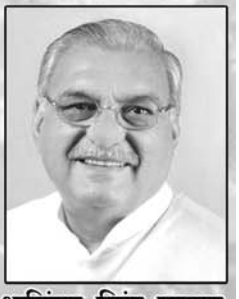

भूपिंदर सिंह हुड्डा
15 सितम्बर 1947

पी. चिदम्बरम
16 सितम्बर 1945

नरेन्द्र मोदी
17 सितम्बर 1950

महेश भट्ट
20 सितम्बर 1948

करीना कपूर
21 सितम्बर 1980

प्रेम चोपड़ा
23 सितम्बर 1935

कुमार सानू
23 सितम्बर 1957

मनमोहन सिंह
26 सितम्बर 1932

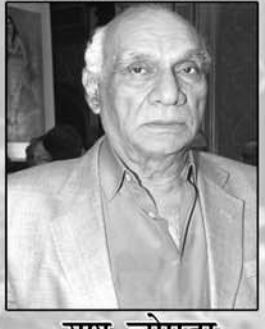

यश चोपड़ा
27 सितम्बर 1932

लता मंगेसकर
28 सितम्बर 1929

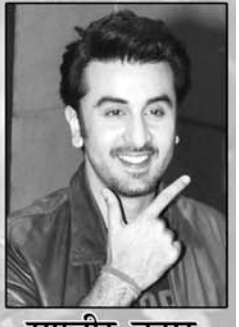

रणवीर कपूर
28 सितम्बर 1982

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पुलिस - प्रशासन मिलकर करते हैं

डिस्को

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

प्रकृति की गोद में खनीज संपदाओं से लवरेज झारखंड प्रदेश को आजादी के बाद से ही जिसको जब अवसर मिला जमकर लूटा गया है। झारखंड काले हीरे का प्रदेश कहा जाता है और काले हीरे का कारोबार करने वाले सफेदपोश लोग होते हैं जिनके दामन पर दाग नहीं लगता इसके लिए इनको सिर्फ डिस्को करना पड़ता है। दामोदर नहीं के उद्गम से समाप्ति तक कोयला का भंडार है और इस भंडार के रक्षक ही जब इसको लूटने वाले से मिलकर डिस्को करने लगे तो फिर इस संपदा को कौन बचायेगा? इस डिस्को के खेल में राज्य एवं केन्द्र सरकार के बड़े-बडे आका भी शामिल रहे और कोलगेट घोटाले ने कांग्रेस की साख को गिरा दिया लेकिन BJP की सरकार में भी डिस्को का खेल जारी रहा है। डिस्को का मतलब किसी फिल्म का डांस के विषय में नहीं लिखा जा रहा है बल्कि कोयला चोरी की तकरीब का दूसरा नाम डिस्को है। डिस्को के खेल में सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि पुलिस-प्रशासन, सांसद-विधायक भी इसमें शामिल रहते हैं और इसकी पुष्टि करनी है तो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके डिस्को क्षेत्र में कार्य कर चुके लोगों की जांच करा दी जाये तो मामला आईने की तरह दिखने लगेगा। डिस्को झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है लेकिन डिस्को को करना सब यही चाहते हैं।

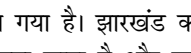

कोयला की कालाबाजारी का दूसरा नाम है **डिस्को**। अब आप यह सोच रहे हैं कि डिस्को तो किसी फिल्म का हिस्सा होगा लेकिन देश के भीतर झारखंड हो या फिर अन्य कोई प्रदेश वहाँ पर कोयले की बड़े स्तर पर चोरी होती है और अकेले झारखंड में प्रतिदिन लगभग एक लाख टन से अधिक कोयला की चोरी डिस्को के द्वारा होता है और अब यह डिस्को क्या है, उसको समझना पड़ेगा की किस प्रकार इस **डिस्को** के खेल में सरकार, विपक्ष के साथ-साथ पुलिस-प्रशासन भी शामिल होते हैं और सरकारी राजस्व पर कैसे सबके मिलीभगत से डाका डाला जाता है और पकड़े जाने पर गरीब हैं कहकर राजनीति की जाती है। आप कोयला के क्षेत्र में जायेंगे तो आपने देखा होगा कि सायकिल पर 10-10 बोरी कोयला लेकर खाद्दान से दूसरे स्थल पर डंप किया जाता है और उसको ट्रक पर 20 टन - 30 टन लोड करके पुलिस-प्रशासन से सांठ-गांठ करके अन्य राज्यों में बेच दिया जाता है और वह चोरी का कोयला सड़क पर आते-आते एक नम्बर का कोयला बन जाता है, (पेपर बनकर तैयार हो जाता है) इसी खेल को हीं **डिस्को** कहते हैं। छोटे व्यापारी की बात तो दूर रूंगटा ब्रदर्स पर जिले के कई थानों में अवैध कोयले के धंधे को लेकर कई मामले दर्ज हैं। कोयले का अवैध धंधा जब जोरो पर होता है तो केन्द्र एवं राज्य सरकार कभी कभार उपर से काफी प्रेशर देती है और इसपर काबू पाने का दावा करती है लेकिन सच सभी जानते हैं कि इस पूरे खेल में सब चोर-चोर मसौरे भाई साबित होते हैं। बदनाम होने की स्थिति में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया जाता है लेकिन अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा पुलिस के हिस्से में भी पहुंचती है जिसकी वजह स मामले पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होती क्योंकि माफिया सफेदपोश लोगों का नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं। फैक्ट्रियों के नाम पर कोल लिंकेज के जरिए भी अच्छी खासी कमाई की जाती है और फैक कंपनी के नाम पर कोयले का आवंटन का खेल कई दशकों से जारी है। पहले अंग्रेजों ने लूटा और आजाद भारत में सरकार एवं माफिया भी इस खेल में किसी से पीछे नहीं हैं। अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन कर साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, डंपर से फैक्ट्रियों में गिरवाने लगे। अधिक भंडारण के बाद जितना कोयला फैक्ट्री के प्रयोग में आया, उसके बाद कोयले को बाहर मंडियों में बेचा जाने लगा। भारी मुनाफा शुरू हुआ, देखते ही देखते पांच से दस साल के अंतराल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक माफिया बनते जा रहे हैं। इसका बड़ा सिंडिकेट हैं और पूरा मामला केन्द्र एवं राज्य की सरकार के साथ-साथ पुलिस प्रशासन के सज्ञान में है और सबको बराबर का हिस्सा पहुंचता है इस वजह से कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं होती और कभी कभार भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ जनता के बीच लोकप्रियता के लिए कार्रवाई की जाती है जिसको बाद में मैनेज कर लिया जाता है। विधायक एवं सांसद सहित पुलिस - प्रशासन और माफियाओं के साथ मिलकर डिस्को पेपर बनाकर तस्करी का खेल निरंतर जारी है। फर्जी कागजात तैयार करके कोयला का काला खेल जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी का लेटर पैड का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ न कुछ ऐसा सामग्री पासिंग के लिए किया जाता है जिसको दिखाकर पुलिस उस लाईन को क्लियर करता है। एक गाड़ी एक सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंचाने का एक पैड की रकम तय होती है उसी को डिस्को कहा जाता है जिसको आमजनता नहीं समझ पाती। देश के भीतर वैसे तो उन सभी राज्यों के सांसद एवं विधायक जिस क्षेत्र में कोयला का भंडार है उसकी संपत्ति की जांच करा लिया जाये तो स्पष्ट हो जायेगा की वेतन एवं अन्य मद में मिलने वाली राशि से कई लाख गुणा राशि की यह मालिक कैसे बने है। डिस्को डांसर ठुमका लगाने के बाद भी वह राशि हासिल नहीं कर पाते जितना यह एक सीमा से दूसरी सीमा तक डिस्को पेपर बनाकर कमाते हैं। पूरा डिस्को इतनी चतुराई से होता है और इसके बाद भी किसी ने इस मामले को उजागर करने का प्रयास किया तो उनका भी राम नाम सत्य हो जाता है। डिस्को के असली मास्टर माईड पुलिस प्रशासन ही है और माफिया सिर्फ मोहरा.....

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 14, अंकः- 159 माहः- सितम्बर 2024 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565
Kamod Kumar Kanchan 8971844318

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

अगस्त 2024

हिन्दू-मुसलमान

मिश्रा जी,

अगस्त 2024 अंक में केवल सच टाइम्स पत्रिका का संपादकीय ''**हिन्दू-मुसलमान में फंसा हिन्दुस्तान**'' काफी मार्मिक एवं चिन्ताजनक लगा की किस प्रकार देश के भीतर सत्ता प्राप्ति के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर भारत को बांटने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में धार्मिक वातावरण की वजह से 100 करोड़ वाला हिन्दू की राजनीति करने वाला भाजपा सरकार बनाने के लिए 272 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी जबकि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। वर्त्तमान समय में बेरोगारी से भी बड़ी समस्या भारत देश में हिन्दू-मुसलमान का बन चुका है।

● **दीपक उपाध्याय, अस्सी घाट, बनारस**

बगावत

संपादक महोदय,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूं और अगस्त 2024 अंक में अमित कुमार की खबर ''**झामुमो में दिखने लगा बगावत**'' ने झारखड की वर्तमान सरकार एवं सोरेन की राजनीतिक पारी पर बेबाक टिप्पणी के साथ खबर को लिखी है। हेंमत सोरेन और चम्पई सोरेन की राजनीतिक हिस्सेदारी पर सटीक विश्लेषण अमित कुमार ने किया है और बताने की कोशिश की है कि इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा और इसका लाभ किसको किस रूप में मिलेगा। केवल सच टाइम्स पत्रिका की सभी खबर पठनीय है और ऐसी खबरो को प्राथमिकता से प्रकाशित करें।

● **मनोज उरांव, खेलगांव मोड़, राँची, झा०**

अन्दर के पन्नों में

10

दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री.....14

25

हत्या फिर बलात्कार

संपादक महोदय,

देश के भीतर महिलाएं काफी असुरक्षित हो चुकी हैं और फांसी की सजा होने के बाद भी रेप के बाद हत्या की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। अगस्त अंक 2024 में अमित कुमार की खबर ''**हैवानियत की हदें पार प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या फिर बलात्कार**'' में पश्चिम बंगाल की सरकार एवं कार्रवाई पर सटीक विश्लेषण करते हुए लिखा गया है जो पठनीय है। इस प्रकार की घटना से देश की अस्मिता पर सवाल उठता है जहां नारी को देवी का रूप माना जाता है उसी देश में उसका पहले बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। विलंब से मिलने वाला न्याय के कारण अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। चिंतनीय खबर लगा।

● **आमोद सक्सेना, बाबू बाजार, कोलकात्ता**

यूक्रेन-रशिया

संपादक महोदय,

पीएम मोदी ने यूक्रेन एवं रूस की यात्रा करके यह साबित कर दिया है कि वर्त्तमान समय में जहां विश्व तृतीय विश्वयुद्ध की भूमिका में है वहीं भारत देश के भीतर धार्मिक उन्माद के बाद भी अन्य देशों की मध्यस्था की स्थिति में है और सभी देश भारत एवं पीएम मोदी का मुरीद होता जा रहा है। केवल सच टाइम्स पत्रिका के अगस्त 2024 अंक की यह खबर वास्तव में भारतवासियों के लिए गर्व करने वाला पल है जहां गोली-बारूद की भाषा को महत्व दिया जा रहा है वहां मोदी का संवाद कितना कारगर साबित हो रहा है। इस अंक का कानूनी सलाह भी पठनीय एवं संग्रहणीय है।

● **मधुसूकदल सहाय, द्वारका, सेक्टर-8, नई दिल्ली**

विरोध

मिश्रा जी,

अगस्त 2024 के केवल सच टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित खबर ''unified pension scheme का विरोध क्यों'' में केन्द्र सरकार का विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। मोदी सरकार की यूपीएस स्कीम और एनपीएस स्कीम को लेकर काफी जटिलताएं देखने को मिल रही है जबकि कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं लेकिन मोदी की सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के बजाय यूपीएस स्कीम को लागू करके एनपीएस से ज्यादा लाभकारी साबित होगा की बात को बताया जा रहा है। अब कर्मचारियों को सोचना है की वह किसी स्कीम में रहेंगे। खबर पठनीय है लेकिन सरकार का यह प्रयास कर्मचारी हित में नहीं दिखता।

● **प्रेमशंकर बरूआ, टावर चौक, भागलपुर**

बस दुर्घटना

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका देश-विदेश की खबरों को भी प्राथमिकता से स्थान देता है और अगस्त अंक में नेपाल में हुए बस दुर्घटना में 17 लोगों की मौत की खबर को पूरी गंभीरता के साथ प्रकाशित किया है। 17 भारतीय नागरिक की इस दुखद घटना को पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और उनके परिजन के साथ सरकार खड़ी है का भरोसा दिलाया है। केवल सच टाइम्स पत्रिका सभी विषयों को केन्द्रीत करके खबर बनाती है जिसकी वजह से इसके पाठक सभी वर्ग के लोग है। केवल सच टाइम्स पत्रिका का पृष्ठ रंगीन हो जाये तो इसकी सजावट भी काफी आकर्षक लगेगा। मुझ यह पत्रिका बहुत अच्छा लगा है।

● **मोहित मेहता, सक्टर-6, बोकारो, झारखंड**

32

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

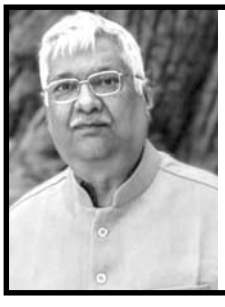

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
व्यवसायी
पटना, बिहार
7360955555

एक नजर

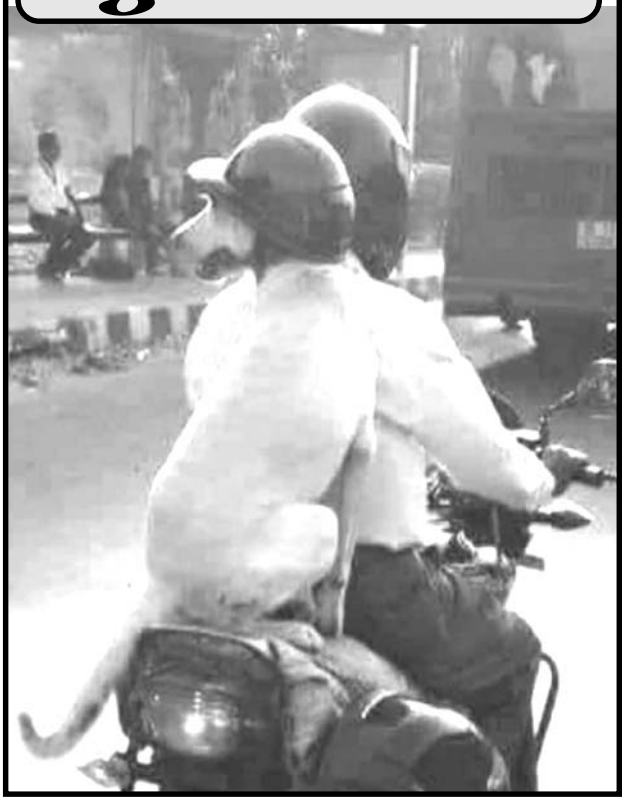

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन?

● विकास सिंह

विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। भाजपा इस वक्त पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। भाजपा ने सदस्यता अभियान में इस बार 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 2 सितंबर को भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा का सदस्य बनाकर की। इस मौके पर ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन चुनाव का एलान करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान के बाद पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

☞ **राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब?**-भाजपा का सदस्यता अभियान तीन चरणों में चल रहा है। प्राथमिक सदस्य बनाने हेतु सदस्य अभियान का पहला चरण 2 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को पूरा हो रहा है। वहीं भाजपा सक्रिय सदस्य बनने के लिए 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भाजपा मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। मंडल और जिला अध्यक्ष चुनाव के बाद राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद एक दिसंबर से प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और 50 फीसदी राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों में संगठन का चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। ऐसे में दिसंबर को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना तय माना जा रहा है।

☞ **जेपी नड्डा के बाद कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष?**- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। भाजपा की 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति के अनुसार अब जेपी नड्डा की जगह नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। जून 2019 में जेपी नड्डा को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष और जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। जेपी नड्डा का बतौर भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका था लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अध्यक्षीय कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया था और 30 जून को उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर अटकलें लगाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे है जिसके परिणाम भी भाजपा की अंदरूनी सियासत

पर बहुत कुछ असर डालेंगे, ऐसे में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर निगाहें लगी है। दिग्गजों के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद बढ़ा संशय-भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ में शामिल भाजपा के कई दिग्गजों के मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नए अध्यक्ष के नाम को लेकर संशय बढ़ गया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में काफी आगे था लेकिन वह मोदी सरकार में कृषि जैसे अहम विभाग का कामकाज संभाल रहे है। वहीं वहीं हरियाणा के के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में था लेकिन वह भी मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बन गए। ऐसे में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह बड़ा सवाल है। भाजपा

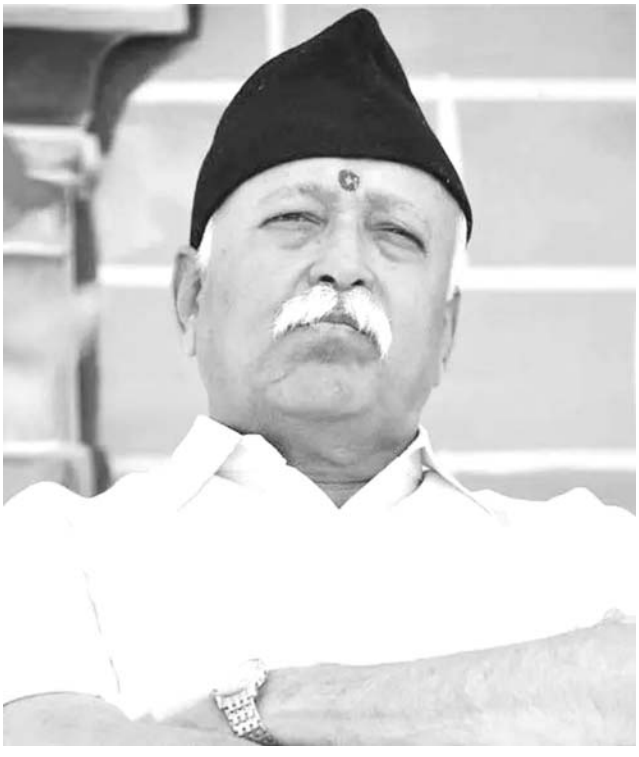

का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत से होगा या दक्षिण भारत से यह भी बड़ा सवाल है। वहीं क्या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते समय लोकसभा चुनाव का भी मूल्याकंन करेगी और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आ सकता है जहां 2027 के शुरुआती चुनाव होना है।

☞ **संघ के पंसद वाले इन चेहरों में से बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष?**-भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पंसद का नेता होगा। लोकसभा चुनाव में संघ और भाजपा में जिस तरह की दूरियां दिखाई दी और उसका नुकसान पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में उठाना पड़ा। सियासत के जानकार बताते है कि संघ का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में घर बैठ गया जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा और वह राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में

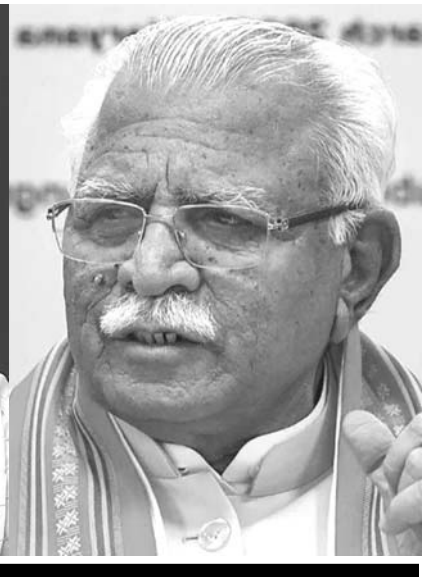

भाजपा अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम के मायने

● वृजेन्द्र सिंह झाला

लंबे समय राजनीतिक वनवास भोग रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक संजय जोशी का नाम अचानक भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उभरकर आया है। यह एक संयोग है या फिर किसी खास रणनीति का हिस्सा, इस पर फिलहाल अटकलें ही चल रही हैं। लेकिन, भाजपा की वर्तमान राजनीति में यह नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, उनकी गिनती कुशल संगठकों में होती हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ बिलकुल भी पटरी नहीं बैठती। जोशी के बारे में कभी उनके सहयोगी रहे गोरधन झड़ाफिया ने कहा था- 'अपार क्षमता वाले एक मूक कार्यकर्ता हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं'।

☞ **भाजपा को बहुत अच्छे से समझते हैं जोशी :-** मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के 'मैकेनिज्म' को भी बखूबी समझते हैं। वे संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989-90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि नरेन्द्र मोदी संगठन मंत्री के रूप पहले से ही काम कर रहे थे। दोनों ने ही मिलकर पार्टी को मजबूत किया और 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए मोदी और जोशी का नाम भी चला था, लेकिन दावेदारी में दोनों पिछड़ गए। तब केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के नाम मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरे थे। मोदी और जोशी ने केशुभाई का साथ दिया था। लेकिन, दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिला और सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री पद पाने में सफल रहे। इसी बीच मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और जोशी संगठन महामंत्री बन गए। इसके साथ ही गुजरात में उनका दबदबा भी बढ़ गया।

☞ **...और दोनों के बीच दूरियां बढ़ीं :-** गुजरात में 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई। कहा जाता है कि मोदी उस समय गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसी के बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। केशुभाई फिर राज्य के सीएम बने। 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी की गुजरात में वापसी हुई और वे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। कहा जाता है कि मोदी ने गुजरात लौटने के बाद संजय जोशी को दिल्ली रवाना करवा दिया। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2001 से 2005 के कार्यकाल में जोशी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का काम किया। सीडी विवाद के बाद जोशी नैपथ्य में चले गए।

☞ **संघ के करीब हैं जोशी :-** जोशी और मोदी के संबंधों की खटास किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन जोशी कई मौकों पर मोदी की तारीफ कर चुके हैं। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीब हैं। वे पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी हैं। जेपी नड्डा के बयान कि भाजपा अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में नाराजगी है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे। यदि जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर भी शिकंजा कस पाएगा। हालांकि यह भी सही है कि जोशी की भाजपा में वापसी आसान नहीं होगी।

अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती संघ को साधने की होगी। ऐसे में बहुत संभावना है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पसंद का ही नेता होगा। संघ के प्रमुख चेहरों में ये नाम हो सकते हैं :-

☞ **सुनील बंसल**-लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है ऐसे में अब भाजपा का पूरा उत्तर प्रदेश में है। सदस्यता अभियान में उत्तर प्रदेश अब तक एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाकर सबसे उपर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके सुनील बंसल को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। संघ के करीबियों में गिने जाने वाले सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया था। ओडिशा में पार्टी ने 24 साल से सत्ता में काबिज बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर पहली बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील बंसल ने देश भर में कॉल सेंटरों को भी संभाला, फीडबैक एकत्र किया और जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।

☞ **केशव प्रसाद मौर्य**-वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस

सुनील बंसल

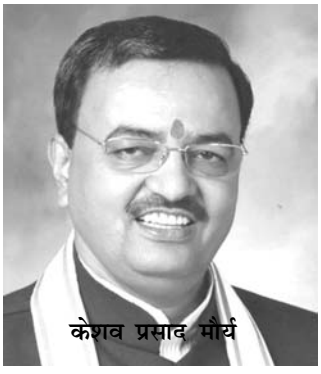
केशव प्रसाद मौर्य

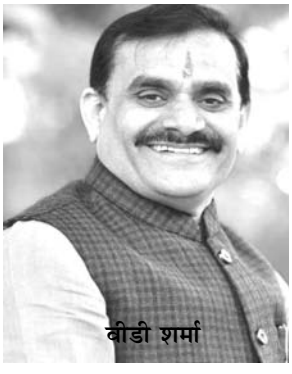
वीडी शर्मा

विनोद तावड़े

तरह से ओबीसी वोटर्स भाजपा से छिटक गया है, उसको देखते हुए भाजपा केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। केशव प्रसाद मौर्य की गिनती भी संघ के करीबी नेताओं में होती है और 2017 में उत्तर प्रदेश में पार्टी की अगुवाई करते हुए उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया था और पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाए थे।

☞ **वीडी शर्मा**-भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में मध्य प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे वीडी शर्मा का नाम भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी शर्मा के संगठन क्षमता की तारीफ की थी। वीडी शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह से मध्यप्रदेश भाजपा ने 64 हजार से अधिक बूथ पर पार्टी का मजबूत नेटवर्क किया और बूथों का डिजिटाइलजेशन किया उस मॉडल को देश के अन्य राज्यों में भाजपा ने लागू किया, वह वीडी शर्मा की संगठनात्मक क्षमता को दिखता है। इसके साथ ही वीडी शर्मा के पक्ष में सबसे मजबूत पहलू उनको संघ का समर्थन हासिल होना है।

☞ **विनोद तावड़े**-वहीं भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी राज्य महाराष्ट्र से भी आ सकता है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने है और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र भाजपा की सीटें काफी कम हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र को अब काफी तवज्जो दी जाने लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं उनका नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ में है। विनोद तांवड़े ओबीसी समाज से आते हैं, जो वर्तमान में बिहार के प्रभारी महासचिव हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि भाजपा बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। ऐसे में जब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने है तो पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है।

☞ **अनुराग ठाकुर**-भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। हिमाचल से आने वाले अनुराग ठाकुर को मोदी 3.0 सरकार में जब मंत्री नहीं बनाया गया तब से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे है। अनुराग ठाकुर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके है और मोदी 2.0 सरकार में वह अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके है।

☞ **बीएल संतोष**-भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ मे है। बीएल संतोष आरएसएस के बड़े प्रचारक भी रह चुके हैं और संगठन महासचिव के तौर पर उनकी पार्टी पर तगड़ी पकड़ है। बीएल संतोष को परदे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है और अगर भाजपा दक्षिण भारत से किसी चेहरे को आगे करती है तो उसमें बीएल संतोष का नाम सबसे आगे होगा।

☞ **के. लक्ष्मण**-दक्षिण के राज्य तेलंगाना के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान में पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण भी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। भाजपा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दक्षिण के राज्यों में ओबीसी वोट बैंक को साध सकती है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार में सहयोगी है, ऐसे में अब पार्टी की नजर तेलंगाना पर भी होगी।

☞ **संजय जोशी**- वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का वक्त जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है वैसे-वैसे नए नाम भी सामने आते जा रहे है। अध्यक्ष की रेस में पिछले दिनों में आरएसएस प्रचारक संजय जोशी का नाम भी तेजी से सामने आया है। संजय जोशी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के तौर पर पर पार्टी को काफी मजबूत किया था। 2001 से 2005 के कार्यकाल में उन्होंने भाजपा को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मजबूत किया। हलांकि संजय जोशी का नाम कथित सीडी विवाद में आने के बाद उनको पार्टी से किनारे कर दिया था, वहीं भाजपा में मोदी-शाह युग की शुरुआत के बाद संजय जोशी अलग-थलग पड़ गए थे। हालांकि संजय जोशी के समर्थन में संघ पहले की तरह अब भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है।

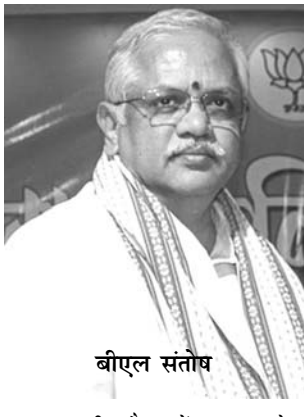
बीएल संतोष

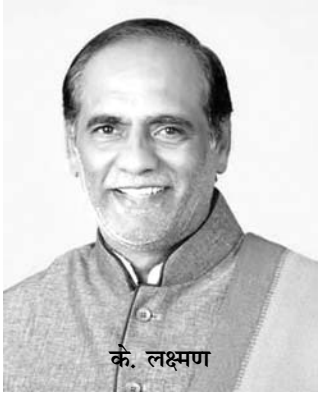
के. लक्ष्मण

अनुराग ठाकुर

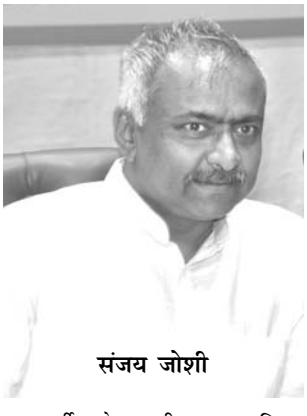
संजय जोशी

अतिशी

दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री

● अमित कुमार

आबकारी घोटाले में लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के (तत्कालिन) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गये। बाहर आने के बाद केजरीवाल के तेवर बदले-बदले थे और उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया।

बता दें कि दिल्ली के (तत्कालिन) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दो दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने की मांग करेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सवाल उठने लगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब होंगे? केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं, तो मुझे बड़ी संख्या में वोट दें। मैं अब चुने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अदालत में आया हूं। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं

भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा, जब लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे। जेल से बाहर आने के बाद अग्निपरीक्षा देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री और सिसोदिया उपमुख्यमंत्री तभी बनेंगे, जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। चुनाव फरवरी में होने हैं। मेरी मांग है कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली में चुनाव कराए जाएं।

बहरहाल, केजरीवाल ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी आतिशी नामित होने के बाद उन्होंने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। बता दे कि केजरीवाल अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। बैठक के बाद आतिशी ने कहा कि हमने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मैं दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करूंगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नामित की गई आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां उन्हें निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने न केवल उन्हें जमानत दे दी, बल्कि केंद्र और उसकी जांच एजेंसियों के खिलाफ कठोर टिप्पणी भी की और उन्हें 'पिंजरे में बंद तोता' बताया। आतिशी ने कहा कि कोई और नेता होता, तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना रहता, लेकिन केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया और इस्तीफा दे दिया। यह हमारे लिए दुख की बात है। उन्होंने कहा कि जनता ने जल्द ही होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री चुनने का संकल्प लिया है। इससे पहले, आतिशी को आप विधायक दल की बैठक में केजरीवाल का

उत्तराधिकारी चुना गया। अरविन्द केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा विभागों वाली मंत्री रहीं आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आतिशी, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आतिशी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलवात ने मंत्री पद की शपथ ली। अहलावत के रूप में नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दलित समुदाय से आने वाले मुकेश अहलावत दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक हैं। शपथ लेने के बाद आतिशी ने केजरीवाल का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण से पहले आतिशी और उनके मंत्रिमंडल में हिस्सा बनने वाले नेताओं ने यहां आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भेंट की। आतिशी, आप नेताओं गोपाल राय, कैलाश गहलोत शपथ ग्रहण से पूर्व यहां सिविल लाइंस में केजरीवाल के निवास पर पहुंचे थे।

गौरतलब है कि आतिशी इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली सभी तीन महिलाओं में सबसे कम उम्र की हैं। वह स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली 17वीं महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। वैसे वरिष्ठ आप नेता आतिशी का मुख्यमंत्री के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। पहली बार की विधायक आतिशी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हैं और उन्होंने आबकारी नीति मामले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में रहने के दौरान आप का कामकाज संभाला। केजरीवाल ने कालकाजी से विधायक आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था। उससे पहले केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। वह दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री हैं। दीक्षित ने जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था तब वह 60 साल की थीं। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के समय 46 साल की थीं। वैसे आतिशी फिलहाल देश में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सनद् रहे कि दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनके कार्यभार संभालने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह रहा कि उन्होंने बैठने के लिए नई कुर्सी चुनीं। वे अरविन्द केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। उस कुर्सी को उन्होंने केजरीवाल के लिए खाली रखा है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चार महीने तक उसी तरह काम करूंगी, जैसे भरत ने भगवान राम की 'खड़ाऊ' को सिंहासन पर रखकर काम किया था। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली के लोग फरवरी में प्रस्तावित चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वापस लेकर आएंगे, तब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी कुर्सी रखी रहेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने राजनीति में गरिमा और नैतिकता की मिसाल कायम की है, भाजपा ने उनकी छवि बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि खाली कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। विधानसभा चुनाव के बाद वे एक बार फिर इस कुर्सी पर बैठेंगे। आगामी चुनाव तक मुख्यमंत्री कार्यालय में केजरीवाल की कुर्सी रखी रहेगी।

एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर मचा बवाल

● संजय सिन्हा

एक बार फिर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया और आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की एक रिक्त सीट पर चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव को अवैध बताते हुए इसका बहिष्कार करने का एलान किया। वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्यपाल को नहीं, केवल महापौर को एमसीडी की बैठक बुलाने का अधिकारी है। पार्टी एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने भी कहा कि कल रात को उपराज्यपाल के निर्देश पर कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि स्थायी समिति के 6वें सदस्य का चुनाव होगा। वह आदेश पूरी तरह से अवैध है। डीएमसी एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उपराज्यपाल के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है कि वे हाउस की मीटिंग में हस्तक्षेप कर पाएं। वही भाजपा ने भी चुनाव प्रक्रिया में खलल डाली थी। मजबूरन सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हम कानून की बात करें तो वैध चुनाव 5 अक्टूबर को ही होंगे। मेयर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हों। भाजपा को समझना होगा कि नगर निगम में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। भाजपा की क्या मंशा है कि रातों-रात चुनाव करवाने की कोशिश की गई? इससे पहले इस पूरे मामले में दिनभर नाटकीय घटनाक्रम रहा जिसमें महापौर शैली ओबेरॉय ने 5 अक्टूबर तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया था, जबकि बाद में उपराज्यपाल ने महापौर का फैसला पलट दिया था। निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने जारी एक आदेश में कहा कि उपराज्यपाल ने स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार समिति की छठी सीट का चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त निगम आयुक्त जितेंद्र यादव को एमसीडी की सदन की बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह सीट भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हो गई थी।

बहरहाल,

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की एक खाली सीट के लिए होने वाले चुनाव से महज एक घंटा पहले महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को इसे स्थगित करने का निर्देश दिया ताकि पूर्व के निर्देशों के अनुसार पांच अक्टूबर को चुनाव कराया जा सके। पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए व्यवधान के बाद महापौर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि, बाद में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार को चुनाव कराने का निर्देश दिया। ओबेरॉय ने एक पत्र में आयुक्त से 5 अक्टूबर को स्थायी समिति के चुनाव में कानून का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आयुक्त से होने वाले चुनाव को अवैध और गैरकानूनी घोषित करने को भी कहा। ओबेरॉय ने आयुक्त को लिखे पत्र में लिखा कि यह आदेश अवैध, असंवैधानिक है क्योंकि यह दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम और दिल्ली नगर निगम (कार्य संचालन और संचालन) विनियम, 1958 की सांविधिक योजना का घोर उल्लंघन है। साथ ही यह निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कसौटी के भी विपरीत है। उन्होंने कहा कि कई पार्षदों ने उन्हें बताया था कि सदन के स्थगित होने के बाद वे शहर से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि आपका आदेश 26/09/2024 को रात 11 बजे जारी किया गया और इतने कम समय में पार्षदों के पास उक्त बैठक में पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने लिखा कि यहां तक कि कई पार्षदों को 27/09/2024 को सुबह 10 बजे तक बैठक की सूचना नहीं मिली। इसलिए, उनसे इतने कम समय में बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करना न केवल जन प्रतिनिधि के रूप में उनके चुनावी अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। आयुक्त के आदेश को घोषित करते हुए ओबेरॉय ने महापौर के रूप में बैठकें स्थगित करने के अपने अधिकार को दोहराया।

'Another proof of the jungle raj': Congress cries injustice, blames NDA for torching of Bihar Dalit colony

Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi and Congress president Mallikarjun Kharge on Thursday termed the "torching of a Dalit colony" in Bihar's Nawada as a horrific incident which has exposed the National Democratic Alliance's "indifference towards the Dalits and deprived". On social media handle X, Kharge said, "The terror of bullies on the Mahadalit colony in Nawada, Bihar is another proof of the jungle raj of the NDA double engine government." "It is extremely condemnable that around 100 Dalit houses were set on fire after firing and everything of the poor families was snatched away," Kharge said. He alleged that the BJP and its allies were indifferent towards the Dalits and the deprived and the state was witnessing in the rise in criminals and anti-social elements. "Prime Minister Modi is silent as usual, Nitish is carefree in his greed for power and the NDA allies are speechless," Kharge said. Meanwhile, condemning the incidents, Rahul Gandhi said, "Burning down an entire colony of Mahadalits in Nawada and destroying the houses of more than 80 families is highlighting the horrifying picture of injustice against the Bahujans in Bihar." "The cries of the Dalit families who have lost their homes and property and the terror created in the deprived society by the echo of the fierce firing were also not successful in waking up the sleeping government of Bihar," Gandhi said. He alleged that such anarchist elements find shelters under the leadership of BJP and its allies. "The silence of the Prime Minister is a seal of approval on this big conspiracy," Gandhi said. He demanded strict action against all the culprits and provide justice to the victim families by rehabilitating them.

Former Arunachal Pradesh hostel warden to be hanged to death for sexual assault on 21 minors, aged 6-14 years

A special court in Arunachal Pradesh on Thursday sentenced to death a former hostel warden who sexually assault 21 minor students in a state-run residential school in Shi-Yomi district between 2014 and 2022. Special Judge (POCSO) Jaweplu Chai handed the death sentence to Yumken Bagra, former hostel warden of Government Residential School, Karo village, Monigong in Shi-Yomi district.

Yumken Bagra

Marbom Ngomdir

Singtung Yorpen

The court also sentenced Singtung Yorpen, the former headmaster, and Marbom Ngomdir, a Hindi teacher at the school, to 20 years' rigorous imprisonment (RI) for abetment of the offense under Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) Act and failing to report it. Bagra was convicted under Sections 328 and 506 (administering poison/harmful substance with the intention of committing an offence, and criminal intimidation) of the Indian Penal Code (IPC) as well as Sections 6, 10, and 12 (aggravated penetrative sexual assault and sexual harassment) of the POCSO Act.

The case came to light in November 2022 when a man lodged a complaint with the Monigong Police Station accusing Bagra of sexually assaulting, harassing, and attempting to rape his 12-year-old twin daughters at the residential school. Bagra (33), a native of Tadin village near Aalo in West Siang district, was arrested on December 13, 2022 in Itanagar 42 days after a case was registered at Monigong PS on November 1 in that year. A Special Investigation Team (SIT) at the Crime Branch Police Station which later probed the case found that Bagra sexually assaulted 21 children, including 15 girls and six boys, aged 6-14 years, between 2014 and 2022 during his tenure as hostel warden at the school. Some of the victims had reported the abuse to former headmaster Yorpen, but he asked them to keep quiet so that the reputation of the school is not denigrated. Two other accused, Tajung Yorpen, another teacher in the same school, and Daniel Pertin, an acquaintance of the hostel warden, were acquitted in the case due to lack of evidence. SIT SP Rohit Rajbir Singh, while acknowledging the immense collaboration and unwavering dedication demonstrated by everyone involved in the pursuit of justice for the victims, said: "This ruling not only addresses the immediate issue at hand but also serves as a critical turning point for the broader societal awareness surrounding the protection of children, reinforcing the collective responsibility to safeguard their rights and welfare." The successful conclusion of this case is a testament to the synergy between the investigation, prosecution, media, and judiciary; all working together to ensure that justice was served, he said.

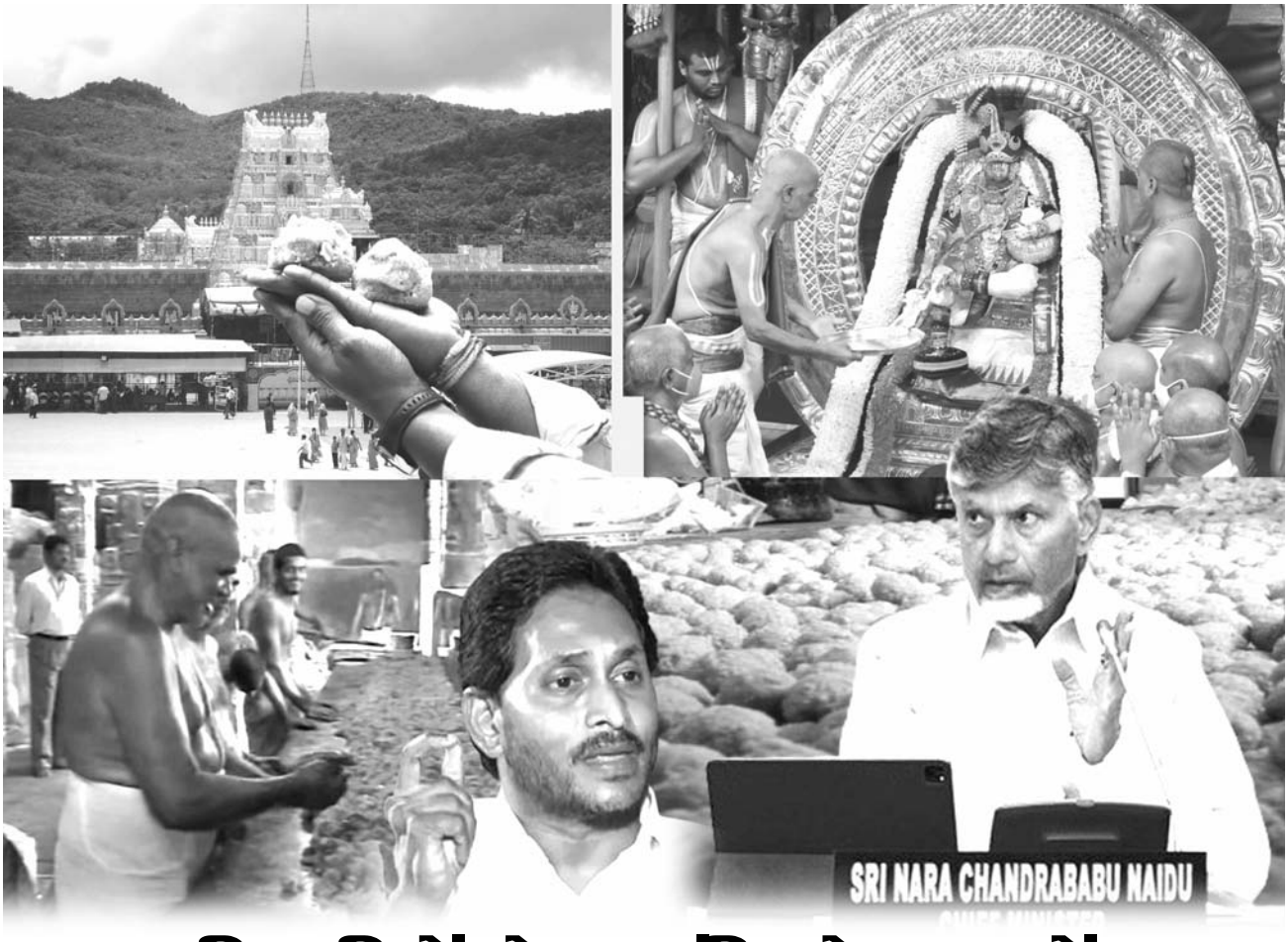

तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में

जानवरों की चर्बी को लेकर सियासी घमासान

तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी को कलियुग का देवता माना जाता है। तिरुमलेश के दर्शन के बाद लोग श्रीवारी लड्डू प्रसादम को ग्रहण करते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी है। तिरुपति में मिलने वाले लड्डू का स्वाद अद्भुत होता है। किसी अन्य लड्डू में ऐसा स्वाद नहीं होता है। लड्डू प्रसाद श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। कोई तिरुमाला के तिरुपति मंदिर जाता है तो उसे प्रसादम लाने के लिए जरूर कहा जाता है। तिरुपति के इस लड्डू के साथ अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसे श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ माना जा रहा है। लड्डुओं की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें पशु चर्बी का उपयोग किया गया। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने दावा किया कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की ओर से उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में पशु की चर्बी, लार्ड (सूअर की चर्बी से संबंधित) और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है।

दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए की एक बैठक में कहा था कि जो तिरुमाला लड्डू मिलता था, वो खराब क्वालिटी का होता था, वो घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे। जब से टीडीपी की सरकार आई है, पूरी प्रक्रिया को साफ किया गया है और लड्डू को गुणवत्ता को सुधारा गया है। टीडीपी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की जा रही है, उसमें कई चीजों की बात कही गई है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीजें लिखी हैं। मगर जिन पर आपत्ति जताई जा रही है, वो लार्ड, बीफ टेलो और फिश ऑयल है।

लार्ड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफेद सा पदार्थ। फिश ऑयल यानी मछली का तेल और बीफ टेलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल। वही टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने दावा किया कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की ओर से उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में पशु की चर्बी, लार्ड (सूअर की चर्बी से संबंधित) और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। नमूने लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। बताते चले कि आंध्र प्रदेश सरकार या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी), जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है की ओर से हालांकि प्रयोगशाला रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों से देवता की पवित्र प्रकृति को नुकसान पहुंचा है और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। दूसरी ओर आंध्रप्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों को प्रसाद में लड्डू दिया जाता है। टीडीपी गुजरात की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी के हवाले से बता रही है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई है। हालांकि एनडीडीबी ने इस पूरे विवाद पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि जो रिपोर्ट शेयर की जा रही है, उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं दिखा है कि प्रसाद का सैंपल तिरुपति मंदिर का है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लड्डू और दूसरे प्रसाद बनाने के लिए जो घी इस्तेमाल होता है, वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दौर में कई एजेंसियों से लिया गया था। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। वाईएसआर सरकार ने लड्डू बनाने में घटिया घी, काजू, बादाम और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप, लड्डू प्रसादम की गुणवत्ता में कमी आई। कर्नाटक की नंदिनी कोऑपरेटिव डेयरी सब्सिडी कीमत पर घी सप्लाई करती थी। नंदिनी कंपनी को पिछली सरकार ने दरकिनार किया, क्योंकि उन्हें घी सप्लाई पर कमीशन मिलता था। नंदिनी द्वारा घी की सप्लाई बंद करना कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के रहते ही तिरुपति को ठेका खत्म किया गया। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि नंदिनी का घी की सप्लाई टीटीडी ने इसलिए बंद करवाई क्योंकि यह महंगा था। अब से नंदिनी पहले की तरह फिर से टीटीडी को घी की आपूर्ति कर रही है।

गौरतलब है कि भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने की प्रथा आज से 300 साल पुरानी है। तिरुपति में जो मंदिर है, वहां पर 1715 से ही भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जा रहा है। यह एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से इस प्रसाद की अहमियत ज्यादा है। इस प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक स्पेशल किचन में बनता है। आंध्र प्रदेश में इसे च्वजन कहते हैं। वही प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को दी जाती है, जो पिछली कई दशकों से बल्कि सदियों से इसी काम में लगे हुए हैं, यानी कि उन लोगों के लिए यह संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह है कि जो इस प्रसाद को बनाते हैं, उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है, सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति रहती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी के अलावा, चना बेसन, चीनी, चीनी के छोटे टुकड़े,

Annexure-1
Lab. Ref. No. AB023654
Sample Name : Ghee
Table- 1. S-Values for sample

Equation No.	S-Value	Standard S value limits as per method
1	**86.62**	98.05 to 101.95
2	**106.89**	99.42 to 100.58
3	**22.43**	95.90 to104.10
4	**117.42**	97.96 to 102.04
5	**19.72**	95.68 to 104.32

Interpretation

- The S value of all equations for sample coded as **AB023654** are **falling out of the range** as prescribed by method.
- If any S-value falls outside the corresponding limits, consider the sample to contain a foreign fat.

Table -2. *S*-value equation for its suspected adulterants as per ISO 17678 : 2019

Equation No.	Foreign fat
1	Soya bean, Sunflower, Olive, Rapeseed, Linseed, Wheat germ, Maize germ, Cotton seed, Fish oil
2	Coconut and Palm kernel fat
3	Palm oil and Beef tallow
4	Lard
5	Total

Note

- Consider the test samples as pure milk fat when all five S-values fall inside the limits mentioned in Table-1.
- However, under the circumstances listed hereafter, a false positive result can be obtained. Hence, the method is not applicable to milk fat in case of:
  - Obtained from bovine milk other than cow's milk, however BIS 16326:2015 mentioned that method given in ISO 17678 may be used for determination of milk fat purity till such a time study for validation and standardisation of GC method as per ISO 17678 for determination of milk fat purity in bovine milk other than cow milk is completed.
  - Obtained from single cow's;
  - Obtained from cows which received an exceptionally high feeding of pure vegetable oils such as rapeseed oil, cotton or palm oil etc.;
  - Obtained from cow suffering from serious underfeeding (strong energy deficit);
  - Obtained from colostrums;
  - Subjected to technological treatments such as removal of cholesterol or fractionation;
  - Obtained from cheeses showing increased lipolysis;
  - Extracted by using the Gerber, Weibull-Berntrop or Schmid-Bondzynski-Ratzlaff methods, or that has been isolated using detergent.

काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का उपयोग होता है। यह प्रसाद इतना खास है कि 2014 में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को लड्डू बनाने के लिए प्रतिदिन 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता है। इसमें काफी धन खर्च होता है जबकि क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इन कंपनियों ने 320 की कीमत पर घटिया घी सप्लाई किया। इसका असर लड्डुओं की गुणवत्ता पर हुआ। पूर्व ईओ धर्मा रेड्डी ने नियमों को ताक पर रख लालच में दूसरी कंपनियों से एग्रीमेंट किया। उन्होंने अपने करीबियों को इसका टेंडर दिया। एक किलो घी कीमत 400 से लेकर 1000 रुपए तक होती है। कुछ कंपनियां तो सिर्फ 320 रुपए की कीमत पर सामने आई। इन कंपनियों की बिना जांच किए एग्रीमेंट किए गए। पिछली सरकार ने मनमानी करते हुए घी की गुणवत्ता की जांचे बिना इसका उपयोग किया। आंध्रप्रदेश में एनडीए सरकार के आने के बाद घी की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजी गई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि इसमें विभिन्न प्रकार के तेल और वनस्पति से निकाला गया तेल था। यह दावा किया गया कि एआर फूड्स तमिलनाडु द्वारा आपूर्ति किया गया तेल प्रयोगशाला में भेजा गया था और इसमें वेजीटेबल ऑइल था। टीटीडी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वही लड्डुओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया।

समिति ने जांच के लिए कुछ सिफारिशें दीं :-

1. 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें।
2. यदि परीक्षण किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया जाता है और स्कोर 7 से 9 अंकों के रिकॉर्ड हो तो ध्यान देना आवश्यक है।
3. 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाली डेयरियों से ही घी खरीदा जाए।
4. उन कंपनियां टेंडर के लायक समझा जाए जो गाय के गुणवत्ता वाले घी की उत्पादन और आपूर्ति करने की तकनीकी क्षमता रखती हों।
5. यह भी जानना जरूरी है कि कंपनियां दूध कहां से खरीद रही हैं। समय-समय पर फील्ड पर जाकर गुणवत्ता की जांच हो और रिपोर्ट भी दी जाए।
6. टेंडर देने वाली कंपनियां यदि कीमत कम रख रही हैं तो पूरे विवरण के साथ हफलनामा लिया जाना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं।

इसमें पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डेयरी विशेषज्ञ, एनडीआरआई, बैंगलोर डॉ. डी. सुरेंद्रनाथ, हैदराबाद के डेयरी विशेषज्ञ विजय भास्कर रेड्डी, आईआईयूएम बैंगलोर प्रोफेसर बी. माधवन, तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉ. स्वर्णलता शामिल थे।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि अब इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने तिरूपति मंदिर में लड्डू के मुद्दे को लेकर छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर से 1 लाख लड्डू अयोध्या भी भेजे गए थे। जिन्हें भक्तों के बीच बांटा गया था। इसे लेकर अयोध्या का संत समाज भी आक्रोशित है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येन्द्र दास, स्वामी रामभद्राचार्य, भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत अयोध्या के संत समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तिरुपति के लड्डुओं में गाय और सूअर की चर्बी मिलाने का आरोप है। अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेन्द्र दास ने अपनी नारजगी व्यक्त करते हुए कहा कि देश में जितने भी तेल-घी बिक रहे हैं, सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मठ-मंदिरों को अपवित्र करने का षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा कि 1857 में जो स्थिति मंगल पांडेय की थी वह स्थिति हमारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। वहीं, कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद व

कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी की योगी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि मैं 2 साल से कह रहा हूं, लेकिन कोई मान नहीं मान रहा है। तिरुपति लड्डू ही नहीं यूपी में बिक रहे देशी घी की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बाबाजी के घी का मैंने नाम ले लिया था। उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया था। वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था कि उन्होंने जांच कराई। वहीं शिक्षाविद और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने साफ तौर पर इस मुद्दे पर कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हिन्दू संस्थानों व मंदिरों को शासकीय नियंत्रण से मुक्त किया जाए और उन्हें हिन्दू आस्था, विश्वास व हिन्दू परम्पराओं पर चलने के लिए स्वतंत्र किया जाए। यही समय की मांग भी है। महाविरक्त आश्रम अयोध्या के महंत माधव दास रामायणी ने कहा कि तिरुपति बालाजी में कोई संत नहीं है। वो कोई मठ नहीं है। इसका संचालन जो ट्रस्ट कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है। ट्रस्ट में किसी एक जाति या धर्म के लोग नहीं हैं। अगर जांच ने चर्बी पाई गई है तो वो सभी लोग दोषी है। राम जन्मभूमि की प्राण-प्रतिष्ठा के समय तिरुपति से आए लड्डू मंदिर में बांटे गए थे। भगवान को भोग भी लगाया गया था। यह सनातन धर्म और हिन्दुओं पर कुठाराघात है। हिन्दू ही अगर हमको मांस खिलाएंगे, हिन्दू ही हमको चर्बी देंगे तो फिर हम अन्य लोगों से क्या अपेक्षा करें? अयोध्या उदासीन आश्रम के महंत डॉ. भरत दास ने कहा कि तिरुपति में जो लड्डू बांटे जा रहे थे, सनातन हिन्दू रीति-रिवाज के विरुद्ध उस लड्डू में पशु चर्बी व मछली का तेल मिलाकर लड्डू बनाया जाता है। हमारी सनातन आस्था व धर्म है। हम लोग साकार को मानने वाले लोग हैं। हम मंदिर ने जाते हैं, भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार उसको हम निर्वाह करते हैं, जिसके फलस्वरूप में प्रसाद मिलता है। तिरुपति में संपूर्ण विश्व के सनातनी जाते हैं। यह सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लगाया जाना चाहिए। यह हमारी आस्था पर कुठाराघात है। इस समय केन्द्र में सनातन की सरकार है और इस समय भी यदि कार्रवाई नहीं हुई तो

मंदिर और प्रसाद का इतिहास?

- 300 साल पुरानी है मंदिर में भोग की प्रथा
- 1985 में भी प्रसाद को लेकर हुआ था विवाद
- 1715 से भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जा रहा
- 2014 में प्रसाद को GI टैग मिला था
- प्रसाद के लिए रोज 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश लगता है
- प्रसाद बनाने वालों को सिर मुंडवाना जरूरी
- सिंगल कपड़ा पहनकर बनाते हैं

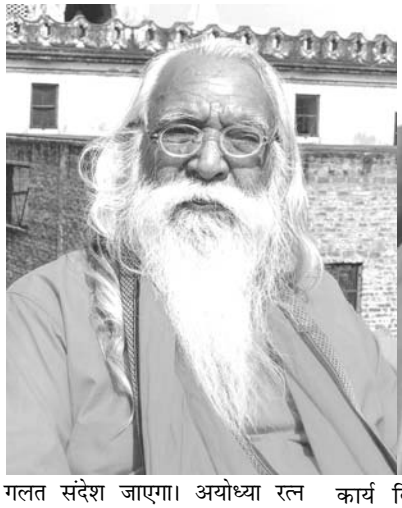

गलत संदेश जाएगा। अयोध्या रत्न सिंहासन राज गद्दी के पुजारी आचार्य विकास दास ने कहा कि अयोध्या में लड्डू तिरुपति ट्रस्ट की ओर से भेजे गए थे। इस मामले में जो भी अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस लड्डू में जिस भी कम्पनी का वनस्पति इस्तेमाल किया गया है उन्हें भी जेल भेजना चाहिए। यह हिन्दू धर्म को बदनाम करने का बड़ा ही जघन्य अपराध है। अयोध्या सीता राम महल के महंत श्याम बिहारी दास ने कहा कि ये हिन्दू धर्म के लोगों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा कार्य किया उसका विनाश होना निश्चित है। अयोध्या के पंडित संतोष मिश्रा ने कहा की जिस प्रकार से तिरुपति के प्रसाद लड्डू में जो अखाद्य चीजें पाई गई हैं, सनातनियों के लिए निंदनीय और दुखद है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सनातनी रोड पर आए तो फिर इस देश का क्या होगा। ये सनातनी रुकने व भागने वाले नहीं हैं।

विदित हो कि इसी प्रसाद को लेकर विवाद पहले भी हुआ है। कई साल पहले एक शख्स ने शिकायत की थी, तब भी गुणवत्ता को लेकर ही सवाल उठा था। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि 1985 में भी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था। तब कहा गया था कि अब प्रसाद को वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाएगा। असल में एक शख्स ने शिकायत की थी कि उन्होंने जो लड्डू खरीदे, उनमें फफूंदी और कील निकली। उस समय इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। अब एक बार फिर उसी प्रसाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे हिंदू आस्था से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहरहाल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप के बाद विवाद बढ़ गया है। विहिप ने इसे गंभीर मामला बताया है जबकि वाईएस शर्मिला ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय महासचिव बजरंग बागड़ा ने निष्पक्ष जांच की वकालत की। उन्होंने आगे कहा विश्व हिंदू परिषद पुरजोर मांग करती है कि इस घटना की पूर्णत: निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से राजनीति का प्रवेश होता है। वहां गैर-हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति से प्रसाद में मिलावट होती है इसलिए हम एक बार फिर मांग करते हैं कि हिंदू पूजा स्थल, मंदिर और तीर्थ स्थान सभी सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए।

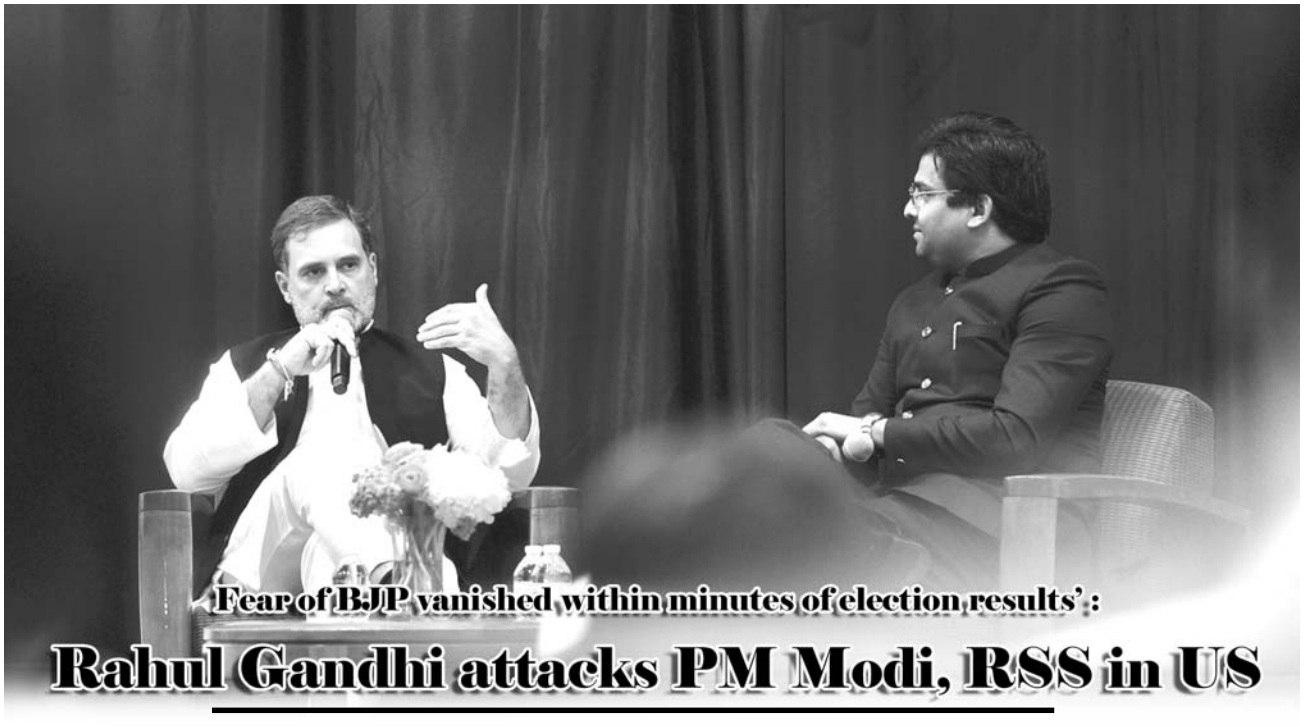

'Fear of BJP vanished within minutes of election results' :

Rahul Gandhi attacks PM Modi, RSS in US

Congress leader and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi on Monday hit out at the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and said that while it "believes that India is one idea, the Congress on the other hand believes that India is a multiplicity of ideas". Addressing the Indian diaspora in Dallas, Gandhi said, "We believe that everybody should be allowed to participate, allowed to dream, and given space regardless of their caste, language, religion, tradition or history."

Stating that the 2024 general election was a huge setback for the BJP, he said, "We saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party." "These are huge achievements of the people of India who realised democracy, of the people of India who realised that we are not going to accept an attack on our Constitution. We are not going to accept an attack on our religion, on our state," he added. Gandhi said that the fight was crystallised in the election when millions of people in India clearly understood that Prime Minister Modi was attacking the Constitution.

"Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. What people understood in the election clearly, and I saw it happening when I used to raise the Constitution, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories," the Raebareli MP said. "In my first speech in Parliament, you must have noticed ,when I describe 'Abhaya Mudra', the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. When I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand, and we are going to make them understand," Gandhi said. Hailing the Indian diaspora, Gandhi said, "You are the people who have come from India, and the values I have been describing — values of the Constitution, values of respect, values of humility — you carry in your hearts; they are in your blood. When you came to this country, you didn't come with arrogance, but with humility. You didn't come with hatred, but with love and affection. You didn't arrive with disrespect, thinking, 'We came to America, who are these people? We will show them.' No, you came with respect. In your hearts are respect, love, and humility".

He termed them as the ambassadors who were a bridge between these two unions — the United States of America and the Union of States, as written in India's Constitution. The former Congress president is on a three day visit to the United States.

पॉक्सो एक्ट में क्या संशोधन चाहता है सुप्रीम कोर्ट, संसद को दिया सुझाव

● बृजेन्द्र सिंह झाला

उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि संसद को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम में संशोधन को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि 'बाल पॉर्नोग्राफी' शब्द के स्थान पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' शब्द का इस्तेमाल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अपराधों की वास्तविकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि इस बीच केंद्र सरकार पॉक्सो अधिनियम में सुझाए गए संशोधन के लिए अध्यादेश पर विचार कर सकती है। पीठ ने कहा कि हम अदालतों को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 'बाल पॉर्नोग्राफी' शब्द का इस्तेमाल किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM) शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

☞ **क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला :** सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि बाल पॉर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' और 'सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम' के तहत अपराध है। पीठ ने अपने 200 पन्नों के फैसले में सुझाव दिया कि व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना संभावित अपराधियों को रोकने में मदद कर सकता है। पीठ के अनुसार, इन शिक्षा कार्यक्रमों में बाल पोर्नोग्राफी के कानूनी और नैतिक प्रभावों के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। फैसले में कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के जरिए आम गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और युवाओं को सहमति एवं शोषण के प्रभाव की स्पष्ट समझ प्रदान की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप और वैसे स्कूल-आधारित कार्यक्रमों को लागू करने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो छात्रों

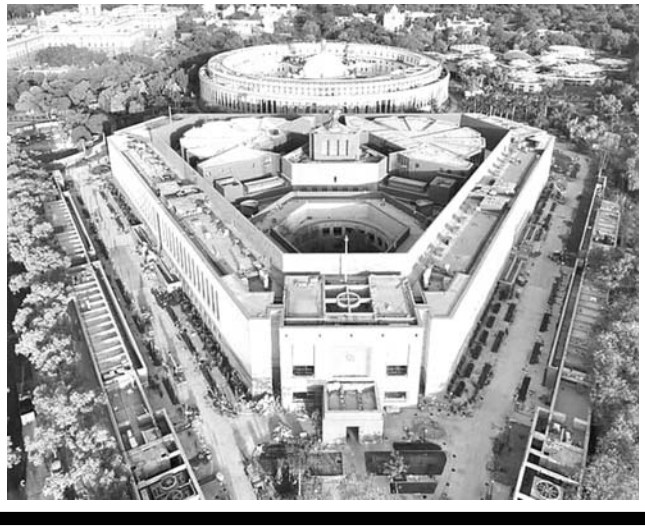

को स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हैं और समस्याग्रस्त यौन व्यवहार (पीएसबी) को रोकने में मदद कर सकते हैं।

☞ **विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव :** पीठ ने कहा कि उपर्युक्त सुझावों को सार्थक प्रभाव देने और आवश्यक तौर-तरीकों पर काम करने के लिए, भारत संघ एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर सकता है, जिसका काम स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम या तंत्र तैयार करने के साथ ही देश भर में बच्चों के बीच कम उम्र से ही पॉक्सो के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी हो, ताकि बाल संरक्षण, शिक्षा और यौन कल्याण के लिए एक मजबूत और सुविचारित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। पीठ ने पीड़ितों को सहायता सेवाएं प्रदान करने और अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता जताते हुए कहा कि इन सेवाओं में अंतर्निहित मुद्दों के समाधान और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सीय हस्तक्षेप और शैक्षिक सहायता शामिल होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि संसद को ऐसे अपराधों की वास्तविकता को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 'बाल पॉर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (सीएसईएएम) से बदलने के उद्देश्य से पॉक्सो अधिनियम में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जो लोग पहले से ही बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री देखने या वितरित करने के क्रियाकलापों में शामिल हैं, उनके लिए 'सीबीटी' (संज्ञानात्मक-व्यवहार थेरेपी) इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देने वाली संज्ञानात्मक विकृतियों को दूर करने में कारगर साबित हुई है। पीठ ने कहा कि थेरेपी कार्यक्रमों को सहानुभूति विकसित करने, पीड़ितों को होने वाले नुकसान को समझने और समस्याग्रस्त विचार पैटर्न को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

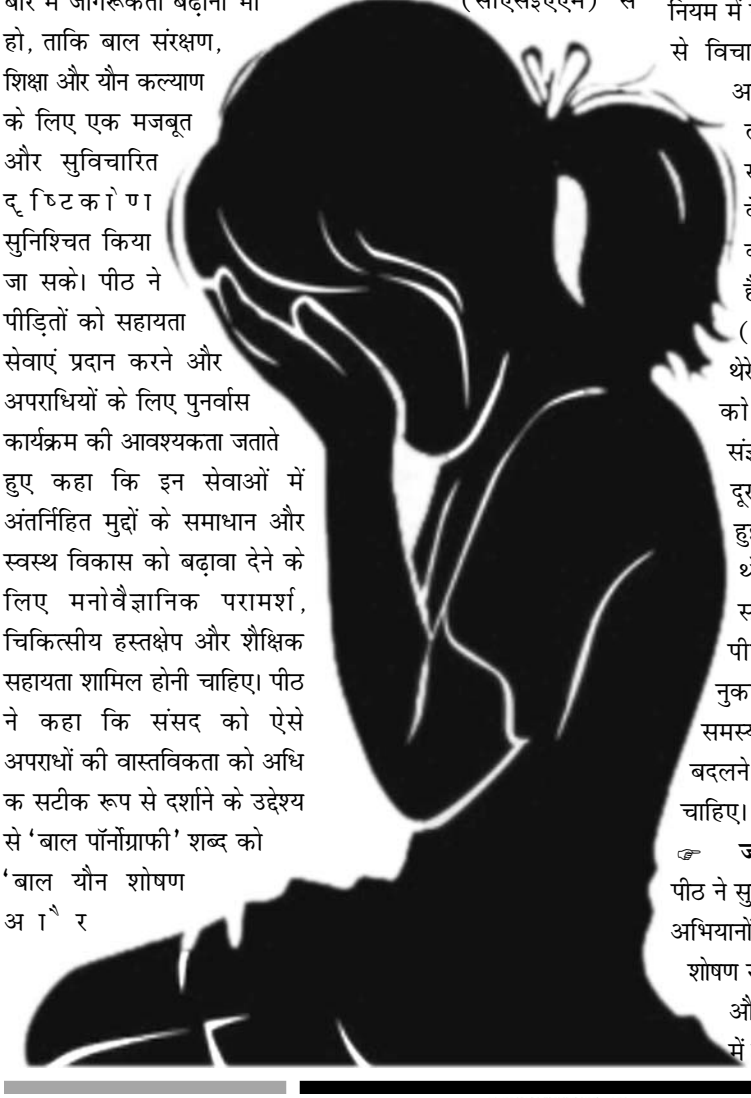

☞ **जागरूकता पर जोर :** पीठ ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से ऐसी घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है और इन अभियानों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने से बचने की प्रवृत्ति समाप्त हो और सामुदायिक सतर्कता को प्रोत्साहित किया जा सके। पीठ ने सुझाव दिया कि शिक्षकों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पीएसबी के संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम इन पेशेवरों को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने तथा उचित तरीके से उसकी जवाबी प्रतिक्रिया देने के तौर-तरीकों को समझने में मदद कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाल पॉर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

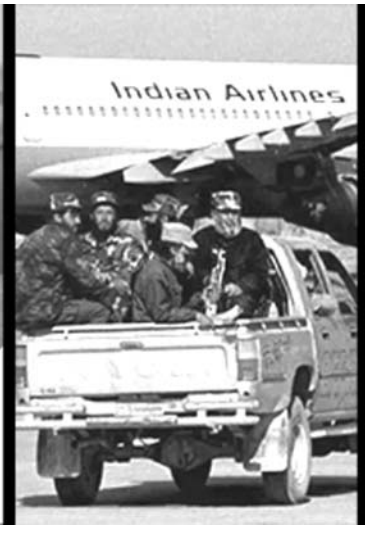

Was part of team dealing with 1984 hijack of plane, realised my father was on board : EAM S Jaishankar

External Affairs Minister S Jaishankar on Friday said that as a junior IFS officer in 1984 he was part of a team which was dealing with the hijacking of an Indian Airlines plane, when he discovered that his father, K Subrahmanyam, was on board the same flight. During an interaction with the Indian community in Geneva, the EAM was asked by a member of the audience about the 'IC 814: The Kandahar Hijack' web series, which has kicked up a lot of controversy over alleged distortion of facts, and why the government is not doing anything about it.

Answering the question, the EAM said that he has not seen it and does not want to comment on it. "To be fair I have not seen the film and I don't want to comment on it. I will tell you something interesting. In 1984 there was a hijacking, I was a very young officer, I was part of the team which was dealing with it," he said, referring to the August 24, 1984, hijack of Indian Airlines Flight 421 by Sikh extremists. EAM said that while the negotiations were on he remembered that it was his turn to go home and feed his baby son lunch.

"Midway through the hijacking, I realised, around 3-4 hours later; those were the days you did not have cell phones; my son was a few months old, my wife used to work, so it was my day to go back home and feed my son at lunch. I rang up mother to say I can't come back home as there is a hijacking. "And then I discovered that my father was on the flight. The flight ended up in Dubai. It's a long story, fortunately nobody got killed but it could have ended up wrongly; so I know, and it is interesting because I was part of the team which was working on the hijacking. On the other hand I was part of the family members who were pressing the government on the hijacking. So actually I had that unique window in both sides in that

sense of the problem." Referring to the recently released web series, the EAM declined to comment.

"And look in movies, the movie guys don't make the government look good, the hero is supposed to look good, not you, I think you have to accept that as part of the cost," he said to laughter. The EAM's father K Subrahmanyam was a prominent international strategic affairs analyst, journalist and former Indian civil servant. On Aug 24, 1984, a domestic flight from the Delhi's Palam Airport to Srinagar Airport with 74 people on board and demanded to be flown to the United States. The plane travelled to Lahore, then to Karachi and finally to Dubai, where the United Arab Emirates negotiated the release of the passengers and the surrender of the hijackers to UAE authorities. To another question about "secret meetings" being held by foreign diplomats with Indian opposition politicians in the country, EAM Jaishankar said: "I would only say this that, in fact I wo uld make it a bigger issue, I'm just giving the larger principles of it; what happens in many countries is that they often practise abroad what they are sensitive to at home. So whenever people abroad do any such thing they must also think about what would happen if this happened in

their own home." On international rankings critical of India, he said: "I have no problem if people comment about our politics, but then in fairness they should also be ready to hear my comments about their politics. And believe me, they have very thin skins about that. "So how to get a more mutually respectful world, everybody says we are equal, but they don't actually behave that way; it's a bit like Animal Farm, some are more equal than others," to laughter from the audience. He said the effort to create a more mutually respectful world is part of the big debates taking place in the world currently.

HORRIFIC! More than 6,000 stones found inside 70-year-old's stomach ; hospital staff takes 2.30 hours to count them

A shocking incident was reported from Rajasthan's Kota city. More than 6000 stones were found in the stomach of a 70-year-old man. Their size ranged from mustard seeds to moong dal and chana dal. It took the hospital staff more than two and a half hours to count them. Doctors of a private hospital in Rajasthan's Kota have successfully removed at least 6,110 gallstones from a 70-year-old farmer from Bundi district.

The farmer from Bundi district had a history of stomach pain, vomiting and other complications for several years but had not

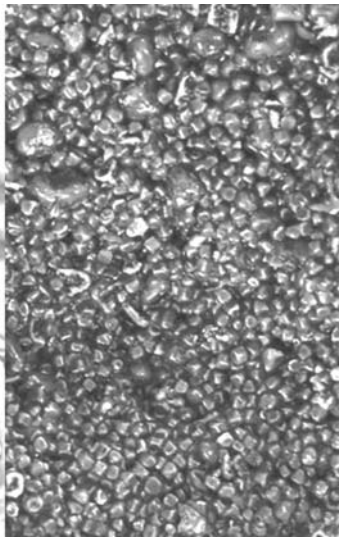

found any relief. Last week, he went to a private hospital in Kota. The sonography revealed that the gallbladder was filled with stones and the size of the gallbladder had almost doubled from 7 x 2 cm to 12 x 4 cm. The doctors performed the surgery and successfully removed at least 6,110 gallstones.

The operation was done on Friday, and the patient was discharged the next day. As per reports, the operation took just 30 minutes, but it took the hospital staff at least two and a half hours to count the stones. "It was a critical case, as the stones in the gallbladder can cause serious harm to the patient. He could have suffered from inflammation in the pancreas, jaundice, and even cancer," Dr Dinesh Jindal, who operated on him, said.

Allegations of being humilated by Nirmala Sitharaman :

Kovai Restaurant seeks to put the matter at rest

After its owner was allegedly humiliated by senior BJP leader and Union Finance Minister Ms Nirmala Sitharaman at a event in Coimbatore two days back during an interaction on GST, which had led to a controversy, the Restaurant has sought to put the matter to rest. As the video of the incident went viral, leaders of various parties, including Congress MP Rahul Gandhi, Party President Mallikarjuna Kharge, Tamil Nadu Chief Minister and DMK President M K Stalin, Opposition AIADMK and allies of the ruling DMK condemned the incident.

Mr Rahul cited the interaction to lash out at the central government over GST and said that a simplified GST with a single tax rate would solve the problems of lakhs of businesses. "When the owner of a small business, like Annapoorna restaurant in Coimbatore, asks our public servants for a simplified GST regime, his request is met with arrogance and outright disrespect", he posted in X. Mr Kharge termed the disgraceful humiliation of a small businessman, the owner of Sree

Annapoorna restaurant in Coimbatore by the Finance Minister and the BJP, smacks of arrogance of power. She has been a repeated offender in such public interactions," he said. Mr Stalin termed it as a shameful incident. Responding to a query from reporters, Mr Stalin said Ms Nirmala had handled the situation in a shameful manner. As the incident triggered a row, Annapoorna, in a statement on Saturday evening clarifying the situation, said its Managing Director D Srinivasan raised the issue of different GST rates for different production in restaurants and bakeries on Thursday.

It said as the video of the interaction with Ms Nirmala Sitharaman went viral the next day, he met her privately under his own volition to ensure there was no misunderstanding or misrepresentation of facts. It said the video of this private interaction was inadvertently shared in social media which has caused a lot of misunderstanding and confusion.

गजब किया सीएम साहब!

डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं और सोशल मीडिया पर हर महीने 54 लाख खर्चा

● नवीन रंगियाल

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर खर्च करने के मामले पर बवाल आया हुआ है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) कथित घोटाले में भाजपा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा चाहती है। जबकि ब्ड इन आरोपों को साजिश बता रहे हैं। इस बीच त्ज् में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि, इस खुलासे का घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ब्ड साहब फिर से चर्चा में जरूर आ गए हैं।

☞ **आरटीआई में खुलासा :** मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फंड की समस्या से जूझ रही कर्नाटक सरकार के मुखिया यानी सीएम सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने पर हर महीने करीब 54 लाख का खर्चा किया जा रहा है। बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट मारलिंगा गौड़ा माली पाटिल ने सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी निकाली है। पाटिल का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि सरकार फंड की समस्या का सामना कर रही है। विकास कार्यों की रफ्तार लगभग थम गई है और विभिन्न विभागों के ठेकेदारों को भुगतान करने में सरकार को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उन्होंने सीएम के सोशल मीडिया अकाउंट पर होने वाले खर्चे के संबंध में आरटीआई लगाई।

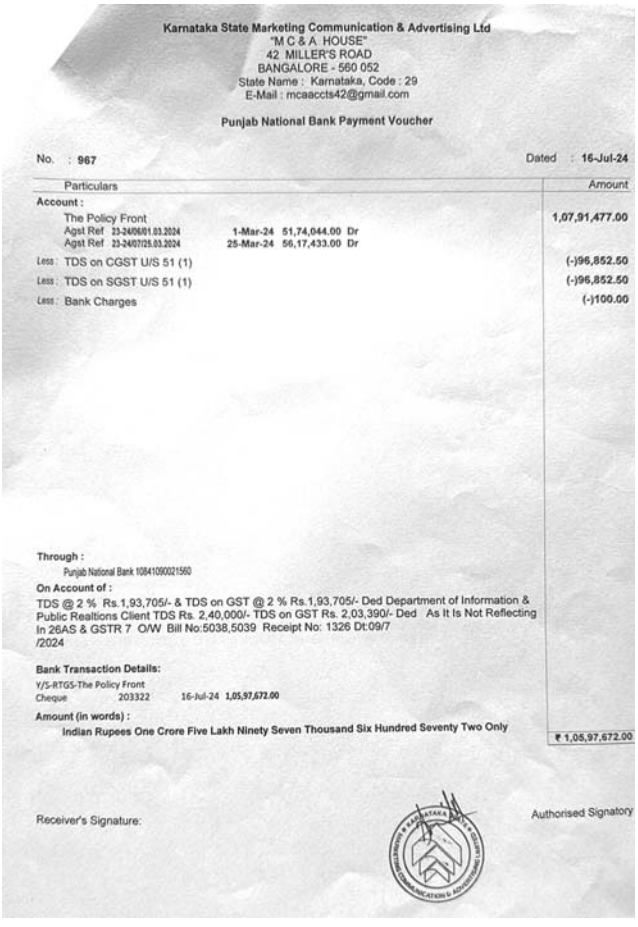

Karnataka State Marketing Communication & Advertising Ltd
"M C & A HOUSE"
42 MILLER'S ROAD
BANGALORE - 560 052
State Name : Karnataka, Code : 29
E-Mail : mcaaccts42@gmail.com

Punjab National Bank Payment Voucher

No. : 967 | Dated : 16-Jul-24

Particulars	Amount
Account :	
The Policy Front	1,07,91,477.00
Agst Ref 23-24/06/01.03.2024 1-Mar-24 51,74,044.00 Dr	
Agst Ref 23-24/07/25.03.2024 25-Mar-24 56,17,433.00 Dr	
Less: TDS on CGST U/S 51 (1)	(-)96,852.50
Less: TDS on SGST U/S 51 (1)	(-)96,852.50
Less: Bank Charges	(-)100.00

Through :
Punjab National Bank 10841090021560

On Account of :
TDS @ 2 % Rs.1,93,705/- & TDS on GST @ 2 % Rs.1,93,705/- Ded Department of Information & Public Realtions Client TDS Rs. 2,40,000/- TDS on GST Rs. 2,03,390/- Ded As It Is Not Reflecting In 26AS & GSTR 7 O/W Bill No:5038,5039 Receipt No: 1326 Dt:09/7 /2024

Bank Transaction Details:
Y/S-RTGS-The Policy Front
Cheque 203322 16-Jul-24 1,05,97,672.00

Amount (in words) :
Indian Rupees One Crore Five Lakh Ninety Seven Thousand Six Hundred Seventy Two Only

₹ 1,05,97,672.00

Receiver's Signature:

Authorised Signatory

☞ **कहां से आ रहा ये खर्चा :** सरकारी एजेंसी कर्नाटक स्टेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड (MCA) ने त्ज् के जवाब में बताया है कि सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने पर हर महीने 54 लाख का खर्चा आता है। हालांकि, उसका यह भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की तुलना में सिद्धारमैया सोशल मीडिया पर बेहद कम खर्च करते हैं। इससे पहले के मुख्यमंत्री का यह खर्चा करीब 2 करोड़ था। पिछले साल 25 अक्टूबर से मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने 3 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए।

☞ **किस कंपनी को दिया जिम्मा :** सीएमओ ने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए हर महीने करीब 53.9 लाख रुपए खर्च किए है, इसमें 18 फीसदी की जीएसटी भी शामिल है। यह भुगतान सिद्धारमैया के अकाउंट हैंडल करने वाली पेमेंट पॉलिसी फ्रंट नाम की कंपनी को किया गया है। कंपनी की लगभग 35 लोगों की टीम सीएम का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती है। गौरतलब है कि राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत कथित घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। इसके बाद से उन पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ है।

जम्मू कश्मीर में कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए मैदान तैयार होने के साथ ही राजनीतिक दल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किए बिना ही मैदान में उतर रहे हैं। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसी पारंपरिक ताकतवर पार्टियां, जिनके नेता पहले भी मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, ने भी शीर्ष पद के लिए अपने उम्मीदवारों को नामित न करने का फैसला किया है। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री पद के जो नाम चर्चा में हैं, उनमें नेकां के उमर अब्दुल्ला, भाजपा के रवीन्द्र रैना, केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नाम प्रमुख हैं। हो सकता है ऐन मौके पर कोई ऐसा नाम भी सामने आ जाए, जो सभी को चौंका दे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कोई भी पार्टी स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने का दावा करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। आंतरिक असंतोष का डर भी एक भूमिका निभा रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना बहुत अधिक है। मौजूदा खंडित राजनीतिक परिदृश्य के साथ, यह प्रतीत होता है कि किसी भी भावी सरकार को गठबंधन की आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही जैसे पिछले दो चुनावों में हुआ था।

☞ **किंगमेकर के रूप में उभर सकती है पीडीपी :** 2014 के चुनावों में, भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, जबकि 2008 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आई थी। इसी तरह, 2002 में कांग्रेस-पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। पीडीपी एक बार फिर खुद को किंगमेकर की भूमिका में लाने की तैयारी में है, क्योंकि अलग-अलग समय पर उसने कांग्रेस और भाजपा दोनों का समर्थन किया है। पिछले सप्ताह बिजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने भी इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में किंगमेकर की भूमिका में उभरेगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलेगा। इल्तिजा ने इस साल 29 अगस्त को मीडिया से कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम जिस भी स्थिति में होंगे, लेकिन पीडीपी किंगमेकर की भूमिका में होगी।

☞ **भाजपा को मोदी से उम्मीद :** एक बात तो साफ है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसलिए राजनीतिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए व्यक्तिगत उम्मीदवारों के बजाय अपने प्रचार अभियान की ताकत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, कांग्रेस राहुल गांधी को अपने प्रमुख व्यक्ति के रूप में लेकर प्रचार कर रही है, जबकि नेकां और पीडीपी क्रमशः फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की विरासत का लाभ उठा रही हैं। छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीतने और सरकार गठन में खुद को अहम खिलाड़ी के तौर पर पेश करने के मौके की तलाश में हैं। भाजपा अपनी राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप, स्पष्ट मुख्यमंत्री उम्मीदवार के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह तथा लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष रहे रवींद्र रैना जैसे कई मजबूत नेताओं के बावजूद, पार्टी काफी हद तक पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की लोकप्रियता पर निर्भर है। भाजपा की प्रचार सामग्री में इन राष्ट्रीय नेताओं को प्रमुखता से दिखाया गया है, और स्थानीय चेहरों ने संभवतः टिकट वितरण के कारण आंतरिक असंतोष के कारण होने वाले विरोध से बचने के लिए पीछे हट गए हैं।

☞ **महबूबा ने मैदान छोड़ा :** पीडीपी के लिए, यह चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि यह अपने संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के बिना पहला विधानसभा चुनाव है। पार्टी आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें कई प्रमुख नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इन असफलताओं के बावजूद, पार्टी मुफ्ती सईद की विरासत पर प्रचार कर रही है, जिसमें महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, इल्तिजा ने साफ कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरी प्राथमिकता मेरा प्रचार अभियान है। मैं लोगों को यह समझाना चाहती हूं कि मैं उनके लिए सही प्रतिनिधि क्यों हूं। मेरे लिए, सीएम बनना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बहुत छोटी हूं, यह बहुत हास्यास्पद लगता है। मेरी प्राथमिकता इन चुनावों को जीतना और लोगों का सच्चा प्रतिनिधि बनना है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि यदि पीडीपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है तो महबूबा मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार हो सकती हैं।

☞ **कांग्रेस की नजर डिप्टी सीएम पद पर :** इस बीच, कांग्रेस ने नेकां के साथ गठबंधन किया है, लेकिन केवल 31 सीटों पर चुनाव लड़ने और 44 के बहुमत के आंकड़े के साथ, पार्टी शीर्ष पद के बजाय उपमुख्यमंत्री की भूमिका के लिए लक्ष्य बना रही है। पार्टी ने हाल ही में अपने प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल की जगह हामिद कर्रा को नियुक्त किया, इस कदम को राहुल गांधी के राष्ट्रीय नेतृत्व में लड़ने की अपनी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, नेकां के गठबंधन का नेतृत्व करने के साथ, कांग्रेस भी अभियान में अहम भूमिका निभाती दिख रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेकां से संभावित दावेदार बने हुए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर सीएम उम्मीदवार के रूप में नामित करने से परहेज किया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में हार ने नेकां के अभियान की गतिशीलता को जटिल बना दिया है। फिर भी, पार्टी अभी भी फारूक अब्दुल्ला के वरिष्ठ नेतृत्व पर निर्भर है, जो अब 80 से अधिक उम्र के हैं, जो पार्टी रैलियों में एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं।

कौन है पोर्न स्टार रिया बर्डे
भारत में रह रही थी, निकली बांग्लादेशी

महाराष्ट्र के उल्हासनगर की हिललाइन पुलिस ने पोर्न स्टार रिया बर्डे को गिरफ्तार किया है। इसका पूरा नाम रिया बर्डे बन्ना शेख है। बता दें कि पोर्न इंडस्ट्री में रिया को आरोही बर्डे या बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि उसने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के प्रोडक्शन में भी काम किया है। रिया भारत में पोर्न स्टार का काम करती है। लेकिन हाल ही में पुलिस ने उसकी पोल खोली है और बांग्लादेशी निकली। उस पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में रहने का आरोप है। पुलिस ने रिया के खिलाफ आईपीसी 420, 465, 468, 479, 34 और 14 ए के तहत मामला दर्ज किया है।

☞ **कौन है रिया बर्डे :** रिया पर आरोप है कि वह मूल रूप से बांग्लादेशी है और वो, उसकी मां, भाई और बहन फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। खास बात यह है बांग्लादेशी होने के बावजूद भारतीय कागजात बनाने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी की थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रिया के अलावा उसकी मां अंजली बर्डे उर्फ रूबी शेख, पिता अरविंद बर्डे, भाई रविंद्र उर्फ रियाज शेख और बहन रितु उर्फ मोनी शेख को भी आरोपी बनाया है।

☞ **क्या रिया की मां ने रची साजिश :** पुलिस के मुताबिक रिया की मां अंजली बांग्लादेश की रहने वाली है और वह अपनी दो बेटियों रिया और बेटे के साथ भारत में अवैध रूप से रह रही थी। रिया की मां ने पश्चिम बंगाल का होने का दावा करते हुए अमरावती निवासी अरविंद बर्डे से शादी की और बाद में खुद और बच्चों के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिक का पासपोर्ट बनवा लिया, ताकि वह अपनी भारतीय पहचान साबित कर सके।

☞ **क्या निकला जांच में :** पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि पोर्न स्टार रिया की मां और पिता दोनों फिलहाल कतर में रह रहे हैं। जबकि पुलिस उसके भाई और बहन की भी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि रिया को पहले मुंबई पुलिस ने वेश्यावृत्ति से जुड़े एक मामले में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। यह पूरा खुलासा तब हुआ जब रिया के दोस्त प्रशांत मिश्रा को पता चला कि वह मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है और देश में अवैध रूप से रह रही है। उन्होंने पुलिस में उसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों की जांच की और पूरी हकीकत सामने आई।

Continual rise of FDI narrating success saga of Make In India: PM Modi at Mann Ki Baat

Prime Minister Narendra Modi on Sunday praised the success of the "Make In India" initiative and urged the country to produce quality products of global standards. PM Modi said the continual rise of FDI in the country is narrating the success saga of the "Make In India" initiative. Make in India campaign has provided an opportunity to people of every class to showcase their talent.

" Today, India has become a manufacturing powerhouse, and it is because of the youth power of the country that the whole world is looking up to us. Every sector of the country's exports is constantly rising. The continual rise of FDI in the country is narrating the success saga of Make in India," he said. PM Modi said Now we are mainly focusing on two things… The first is 'Quality', that is, goods made in our country should be of global standards… and the other is 'Vocal for Local. That means, local products should get maximum promotion." Highlighted the importance of "water conservation." Prime Minister Modi praised the efforts of women to make it a momentum across the country.

PM Modi said, "For the last few weeks, it has been raining heavily in different parts of the country. This rainy season reminds us how important 'water conservation' is." He said, "Water saved during rainy days helps a lot during water scarcity months, and that's the spirit of campaigns like 'Catch the Rain.' The Prime Minister also shared the success stories of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. He said, "In Raipura Village of Dindori, Madhya Pradesh, construction of a large pond has raised the groundwater level considerably. The women of this village benefitted from this." PM Modi also spoke on the popularity of the "Swachh Bharat Mission," saying, "Due to the success of the 'Swachh Bharat Mission' the Waste to Wealth' mantra is becoming popular among people. People have started talking about Reduce, Reuse and Recycle." Calling upon to plant saplings, PM Modi highlighted the success of the 'Ek Ped Maa Ke Naam' initiative. "When our collective participation combines with our determination, it produces amazing results for the entire society. The most recent example of this is 'Ek Ped Maa Ke Naam'," he added.

PM Modi informed that Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Telangana have created a new record by planting more saplings than the set target. "Under this campaign, more than 26 crore saplings have been planted in Uttar Pradesh, 15 crore in Gujarat, and more than 6 crore saplings were planted in Rajasthan in the month of August alone," he added. During the address, the Prime Minister also reflected on the 10-year anniversary of his radio show and said, "This episode today is going to make me emotional. It's flooding me with a lot of old memories... The reason is that this journey of ours in Mann Ki Baat is completing 10 years." He added that the listeners of Mann Ki Baat are the real anchors of this show, and it has proved how hungry the people of the country are for positive information." During his address, PM Modi also spoke on the return of ancient artifacts by the US, said, "We are all very proud of our heritage. I always say 'Vikas Bhi, Virasat Bhi'.

There is a lot of discussion about the return of our ancient artefacts by the US. He added, "US President Joe Biden, very affectionately, showed me some of these artefacts in his private residence in Delaware. Returned artifacts are made of materials such as terracotta, stone, ivory, wood, copper, and bronze."

Highlighting the Make in India initiative, PM Modi said, "Today, it gives me immense joy to see that the poor, the middle class, and MSMEs are getting a lot of benefit from this campaign.' While concluding his show, PM Modi greeted everyone for upcoming festivals and urged them to buy 'Made in India' products during the festival. He asserted that only buying clay-made lamps (diyas) would not achieve the purpose of supporting local traders, we should buy a range of products.

"My views are personal" :
BJP MP Kangana Ranaut withdraws comments on farm laws

BJP MP Kangana Ranaut on Wednesday withdrew her remarks against the three farm laws, saying they were "personal" and did not represent the stand of her Bharatiya Janata Party. Facing a backlash for giving a call to "bring back" the farm laws that were repealed in 2021, BJP MP from Mandi said, "My views on farm laws are personal, and they don't represent the party's stand on those bills." Kangana withdrew her remarks and acknowledged that her statement on the contentious laws may have disappointed many, which she regretted. In a post on X, Ranaut wrote, "When farmers' laws were proposed, several of us had supported them. But with great sensitivity and sympathy, our respected prime minister had withdrawn those laws." "I regret if I left anybody disappointed with my words and opinions. I take my words back," she said. Kangana said, "If I have disappointed anyone with my views and words, I am sorry for that. I take my words back," she added, underscoring the collective responsibility of BJP members to stand by the Prime Minister's judgement.

BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia also said the remarks of Kangana are personal and the party has nothing to do with it. "I want to make it clear that this statement is a personal statement. Kangana Ranaut is not authorised to make such a statement on behalf of the BJP, and it doesn't depict the BJP's view on the farm bills. We disapprove of this statement," he wrote on X. The controversy erupted earlier on Tuesday when Ranaut told the media that , "I know this statement could be controversial, but the three farm laws should be brought back. The farmers should themselves demand it." She argued that the three laws were beneficial for the farmers but were repealed by the Centre in the wake of the protests by farmer groups in some states.

कौन हैं प्रणीति शिंदे
जिनका राहुल के साथ जोड़ा जा रहा है नाम?

सोशल मीडिया खासतौर पर यूट्यूब पर एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है कि राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे शादी करने वाले हैं। यह अफवाह पहले छोटे पूरे यूट्यूब चैनल व्यूज के लिए उड़ाते थे, मगर अब कुछ गंभीर पत्रकार भी ऐसी बातें करने लगे हैं। जिस लड़की के साथ राहुल गांधी का नाम जोड़ा जा रहा है उसका नाम प्रणीति शिंदे है। प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार में रहे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। अभी प्रणीति शिंदे खुद भी महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद हैं। हालांकि अब तक इन दोनों लोगों की शादी की कोई भी खबर नहीं है, जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वो सिर्फ अफवाह मात्र है। जानते हैं आखिर कौन हैं प्रणीति शिंदे जिनका नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोडा जा रहा है।

☞ **पिता महाराष्ट्र के सीएम, केंद्र में गृहमंत्री रह चुके हैं :-** 43 साल की प्रणीति शिंदे राजनैतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र की कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री रहे हैं। वह सोलापुर लोकसभा सीट से तीन बार सांसद रहे। यह सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है। यहां से 11 बार पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। साल 2014 में मोदी लहर के दौरान यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। 2019 में भी भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की। इस बार सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को भेद कर अपने पिता और कांग्रेस की सियासी पिच पर विजय हासिल की है।

☞ **तीन बार रहीं विधायक, अब पहली महिला सांसद :-** प्रणीति शिंदे सोलापुर लोकसभा सीट से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद हैं। वह इससे पहले सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक सफर की शुरुआत जय-जुई विकासमंच सामाजिक संगठन से की थी। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। अब उन्होंने लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर अपना स्थान और ऊंचा कर लिया है। इससे पहले प्रणीति को प्रदेश कांग्रेस ने भी कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में अवसर देकर अच्छी ताकत दी है। प्रणीति ने 2001 में सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से कला में डिग्री के साथ स्नातक किया है। उन्होंने साल 2004 में मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। चुनाव आयोग में दिए हलफनामे के मुताबिक, प्रणीति शिंदे के पास 6 करोड़ 60 लाख 70 हजार 402 रुपए की संपत्ति है। उन पर कोई देनदारी नहीं है। उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। सोलापुर क्षेत्र में प्रणीति शिंदे के लोग जबरदस्त समर्थक हैं।

भारत : समय पर जनगणना क्यों जरूरी है

● आयुष यादव

भारत में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड महामारी की वजह से टाल दी गई लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी इस पर स्थिति अभी साफ नहीं है। 145 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन ये आंकड़े भारत सरकार ने नहीं जारी किए थे बल्कि दूसरी संस्थाओं ने किए। कारण ये कि भारत ने हर दस साल पर कराई जाने वाली जनगणना 13 साल से कराई ही नहीं है।

☞ **जनगणना के मायने क्या हैं** :- प्राचीन रोमन साम्राज्य में सदियों पहले जनगणना के प्रमाण पाए गए थे। जबकि आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके सबसे पहली जनगणना सन 1749 में स्वीडन में कराई गई थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1872 में पहली अनियमित और 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। तब से लगातार हर दस साल पर भारत में जनगणना होती रही है। जनगणना का मतलब है किसी देश में निवास करने वाले सभी लोगों के एक विशेष समयावधि में अलग-अलग मानकों के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका विश्लेषण करने के बाद उन्हें जारी करना। जनगणना के जरिए जो आंकड़े मिलते हैं उनका इस्तेमाल बजट आवंटन, नीति निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण जैसी जरूरी चीजों में किया जाता है।

☞ **पहली बार जनगणना में इतनी देरी** :- भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर दशक में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हालांकि 2021 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी थीं लेकिन 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में भी कोविड महामारी की बात कहते हुए जनगणना न कराए जाने की जानकारी दी थी। शिक्षाविद विजेंदर चौहान कहते हैं, ष्विपक्षी पार्टियों द्वारा जातिगत जनगणना का लगातार मुद्दा उठाना और केंद्र सरकार के घटक दलों का इस पर मुखर होना कहीं न कहीं इस देरी का कारण जरूर है।" उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां जनगणना करवा पाना आसान काम नहीं रहा है और मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान से तुलना करते हुए कई बार इस बात का श्रेय लिया है कि हम इस मामले में उनसे कहीं बेहतर हैं लेकिन अब जनगणना हमारे यहां भी एक राजनीतिक औजार बन चुकी है।

☞ **क्यों जरूरी है जनगणना** :- जनगणना सूचना का एक अहम स्रोत है। इसके जरिए देश के लोगों के बारे में कई तरह की सांख्यिकीय जानकारी हासिल होती हैं। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों, योजनाओं के निर्माण के अलावा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन में किया जाता है। संसद, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। देश में मौजूद बिजनेस सेक्टर और उद्योग भी इन्हीं आंकड़ों के जरिए अपनी पहुंच को बेहतर बनाते हैं। साथ ही वित्त आयोग द्वारा राज्यों को मिलने वाला अनुदान भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। जनगणना होनी क्यों जरूरी है इसका उदाहरण देते हुए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विकास कुमार कहते हैं, ष्कोरोना काल के दौरान जिस तेजी से भारत के कई प्रदेशों से लोगों का प्रवास हुआ, अगर समय रहते हमारे पास उसके बेहतर आंकड़े होते कि किस जिले या प्रदेश से कितनी संख्या में और कितनी अवधि के लिए लोग बाहर गए हैं तो स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन को बेहतर मदद मिलती।"

☞ **आंकड़ों की कमी से कैसी परेशानी खड़ी होती है** :- पॉपुलेशन स्टडीज में पीएचडी कर चुके अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉ। उदय शंकर मिश्र बताते हैं, ''हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें माहिर हैं लेकिन किसके लिए करना चाहते हैं ये हमें पता नहीं है। सरकार कहती है कि हम इतने लोगों को घर दे देंगे लेकिन जब हमारे पास आंकड़े ही नहीं हैं कि

किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोगों को घरों की जरूरत है तो पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं होगा।" भारत में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजनाओं का हाल अच्छा नहीं है। बुजुर्गों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 2021-2030 रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60 साल से ज्यादा की उम्र के चालीस प्रतिशत बुजुर्ग वित्तीय सुरक्षा के मामले में बहुत खराब हाल में हैं और लगभग हर पांचवें बुजुर्ग के पास आय का कोई साधन नहीं है। पिछले दशक से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। प्रोफेसर मिश्र ने डीडब्ल्यू को बताया, ष्शहरी क्षेत्र का मतलब है ऐसा इलाका जहां मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होता है और लोग वहां रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे आंकड़े ही नहीं है कि हम ऐसे नए पैदा हुए शहरी क्षेत्रों की पहचान कर सकें और वहां के लोगों के लिए बेहतर योजनाएं बना सकें।"

☞ **सर्वे नहीं हो सकता जनगणना का विकल्प** :- देश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल नई नीतियों को तैयार करने और पिछली नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अपनी किताब 'नंबर्स इन इंडियाज पेरिफेरी: दि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्सश का हवाला देते हुए प्रोफेसर विकास कुमार कहते हैं, ष्सैंपलिंग फ्रेम और वास्तविक आंकड़े में कई बार बहुत फर्क दिखाई देता है। गरीबी की दर और गरीबी रेखा जैसे मानक इनकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं और इसका सीधा असर पब्लिक पॉलिसी पर पड़ता है।ष वो बताते हैं कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की गई गलती की वजह से वित्त आयोग द्वारा नागालैंड को लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित हो गया था और जम्मू कश्मीर के मामले में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन में गलतियां देखने को मिली थीं। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सर्वे और जनगणना के आंकड़ों की तुलना करते हुए डॉ। विजेंदर चौहान कहते हैं, ष्सर्वे के डेटा पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वे के डेटा को सरकार अपनी मर्जी से जैसा दिखाना चाहे उसे वैसा प्रदर्शित कर सकती है लेकिन जनगणना के साथ ऐसा करना संभव नहीं है।ष वे आगे कहते हैं कि बतौर शिक्षाविद पिछले दस सालों में सरकार से भरोसेमंद डाटा जुटा पाना जटिल काम बन चुका है।

☞ **कब तक इस्तेमाल हो सकते हैं आंकड़े** :- प्रोफेसर विकास कुमार बताते हैं कि हर जनगणना के बाद अगले 25 साल का अनुमान लगा लिया जाता है। इसलिए जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 2036 तक का अनुमान सरकार के पास था लेकिन सिर्फ अनुमान की बदौलत नीतियां तैयार करने से गड़बड़ हो सकती है। प्रोफेसर उदय शंकर कहते हैं, ष्दशकीय जनगणना का डेटा कभी पुराना नहीं होता। यह हमारे लिए कई सालों तक चेकप्वाइंट के रूप में काम आता है। लेकिन जब हम एक दशक आगे बढ़ जाते हैं तो पुरानी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल चेकप्वाइंट की तरह नहीं किया जा सकता क्योंकि काफी चीजें बदल चुकी होती हैं इसलिए जनगणना में देरी कई समस्याएं खड़ी कर सकती है।" जब सरकार अलग-अलग तबकों जैसे - बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किशोरों आदि के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है तो इनका लक्ष्य इन तक समुचित लाभ पहुंचना होता है लेकिन सही आंकड़े के अभाव में न तो ये कार्यक्रम सफल हो सकते हैं और न ही नए कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। जनगणना कराए जाने की जरूरत पर बल देते हुए डॉ विजेंदर कहते हैं, ष्तमाम अंतरराष्ट्रीय निकायों के आंकड़ों के साथ जब भी भारत के आंकड़ों की बात की जाती है तो उसके साथ ये चेतावनी लिखी हुई दिखाई देती है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं या फिर पुराने हो चुके हैं।"

Kolkata doctor case : Mamata Banerjee agrees to remove Kolkata top cop, docs to continue ceasework till formal order

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Monday night agreed to remove Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal, Deputy Commissioner (North) Abhishek Gupta and two senior health officials after a meeting with the protesting junior medics at her residence here. However, the doctors later said they would continue their cease work and sit-in protest outside the health department headquarters Swasthya Bhavan till the government implanted the decisions. Banerjee, describing the over two-hour meeting as fruitful, said a new CP would be named after 4 PM on Tuesday. Goyal will be given a new assignment. She said there will be a reshuffle in the police department. Acceding to another demand from the junior doctors of government medical colleges, who have been on a cease work protest since the alleged rape and murder of a lady medic in her workplace - the R G Kar Medical College and Hospital - Banerjee said the Director of Health Services and the Director of Medical Education would also be removed. Concerning the demand of the junior doctors that justice be given to their deceased colleague, Banerjee pointed out that the case was now being investigated by the federal agency Central Bureau of Investigation (CBI). "The state government will provide all necessary assistance as required for expediting the completion of the inquiry and justice to the deceased," read the minutes of the meeting signed by Chief Secretary Manoj Pant and representatives of the West Bengal Junior Doctors Front, who attended the deliberations. Banerjee also said safety and security in the workplace of the medics would be ensured "Rs. 100 crores have been sanctioned for hospital infrastructure like CCTV, washrooms etc, which will be formalised in close consultation with the medical fraternity. The composition of the Rogi Kalyan Samity (Patients' Welfare Committee) will be revised to make it more inclusive through the inclusion of all stakeholders," according to the minutes. The state government also proposed that a Task Force headed by the Chief Secretary and including the Home Secretary, the DG Police and CP Kolkata as well as representatives of the junior doctors will look into the related matters. "An effective and responsive grievance redressal mechanism will be put in place in the medical infrastructure across hospitals and colleges," the meeting decided. It was jointly resolved to work in close coordination to discuss and resolve all issues faced by the medical fraternity at the level of the Chief Secretary. During the meeting, the chief minister requested the junior doctors to resume their duties. Regarding the medics' demand for removing the state health secretary Narayan Nigam, the CM

told the doctors that removing him would create a vacuum in the health department as two senior officials were already being shunted out. The junior doctors have been holding the sit-in protest outside the Swasthya Bhavan since Tuesday last. The medics said several of the issues were settled, but there were more things to be achieved. "The government has been forced to accept a number of our demands. This is a victory of the common people, doctors, and nursing staff. We thank everybody for standing by our protest like a rock. But we will continue our protest till the government enforces the decisions taken at the meeting," said Debasish Haldar, one of the protestors. The medic said they would also monitor the Supreme Court hearing on the matters linked to the rape and murder which is scheduled for Tuesday. "After the hearing, and once the government issues orders implementing the decisions of themeeting, we will discuss everything in our general body meeting and arrive at a decision". Earlier, the medics had put a dissenting note in the minutes as the government did not agree to their demand for removing the state Health Secretary and the Deputy Commissioner (Central) of Kolkata police. "WBJDF representatives expressed disagreements with regard to no disciplinary actions against DC Central and transfer of Health Secretary. As regards ensuring safety and security, it was intimated by WBJDF that further discussions regarding specific formulations of the same will be required. "It was also proposed that the existing threat culture prevalent in the medical colleges can be removed after further deliberations through specific formulations (democratically elected students unions and RDAs etc)," read the minutes.

From 10th century Apsara idol to 17th century Lord Krishna idol :

297 antiquities stolen, trafficked from India returned by US during PM Modi's visit

On the occasion of the visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States, the US side facilitated the return of 297 antiquities that had been stolen or trafficked from India, including idols of Lord Krishna, Lord Ganesha and the Buddha.

These artifacts will shortly be repatriated to India. In a symbolic handing over, a select few pieces were showcased to Prime Minister Modi and President Joe Biden on the sidelines of their bilateral meeting in Wilmington, Delaware. Prime Minister thanked President Biden for his support in the return of these artefacts. He noted that these objects were not just part of India's historical material culture, but formed the inner core of its civilization and consciousness, a statement said.

The antiquities belong to a time period spanning almost 4,000 years, from 2000 BCE – 1900 CE and have origins in different parts of India. Majority of the antiquities are terracotta artefacts from Eastern India, while others are made in stone, metal, wood and ivory and belong to different parts of the country. Some of the notable antiquities handed over are :

☞ Apsara in sandstone from Central India belonging to 10-11th century CE;

☞ Jain Tirthankar in bronze from Central India belonging to 15-16th century CE;

☞ Terracotta vase from Eastern India belonging to 3-4th century CE;

☞ Stone Sculpture from South India belonging to 1st century BCE-1st century CE;

☞ Lord Ganesh in Bronze from South India belonging to 17-18th century CE;

☞ Standing Lord Buddha in sandstone from North India belonging 15-16th century CE;

☞ Lord Vishnu in Bronze from Eastern India belonging to 17-18th century CE;

☞ Anthropomorphic figure in copper from North India belonging to 2000-1800 BCE;

☞ Lord Krishna in bronze from South India belonging to 17-18th century CE,

☞ Lord Karthikeya in granite from South India belonging to 13-14th century CE.

In recent times, restitution of cultural property has become an important aspect of India-US cultural understanding and exchange. Since 2016, the US Government has facilitated the return of a large number of trafficked or stolen antiquities. 10 antiquities were returned during PM's visit to USA in June 2016; 157 antiquities during his visit in September 2021 and a further 105 antiquities during his visit in June last year. The total number of cultural artefacts returned from US to India since 2016 stands at 578. This is the maximum number of cultural artefacts returned by any country to India.

The artifacts were returned in keeping with close bilateral ties and to foster greater cultural understanding, as part of which the US State Department's Bureau of Educational and Cultural Affairs, and the Archaeological Survey of India under Ministry of Culture, Government of India, had signed a Cultural Property Agreement in July 2024 to fulfil the commitments made by President Biden and Prime Minister Modi to enhance cooperation to protect cultural heritage, as reflected in the Joint Statement issued after their meeting in June 2023, the statement added.

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

☆ अगर कोई नेता अपने भाषण से विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों के बीच नफरत पैदा करने वाला कोई बयान या भाषण देता है तो उसके लिए उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानून में किस प्रकार के सजा का प्रावधान किया गया है ?

यदि कोई व्यक्ति चाहे वह नेता हो या आम पब्लिक हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो वह धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा इत्यादि के आधारों पर समाज के विभिन्न जाति वर्गों या समूहों के बीच शत्रुता या नफरत एवं सौहार्द के वातावरण को खराब करने के उद्देश्य से अगर कार्य करते हैं तो उनके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की ध ारा 196 में बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 में जो वर्णन है उसके अनुसार कोई व्यक्ति जो बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक मूल्य वंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूह जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द, शत्रुता ,घृणा या वह मनुष्य की भावनाएं धर्म मूल वंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर लोगों को भड़काने या उकसाने का प्रयास करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक मूल भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोग शांति में विघ्न डालता है या जिससे कार्य से विघ्न होना संभव हो अथवा कोई ऐसा प्रयास आंदोलन कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक मूल वंशीय भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विभिन्न आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक मूल वंशीय भाषा प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध अपराध इकबालिया हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे जिससे समाज में असुरक्षा डर भय की भावना उत्पन्न होती है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 (1) के अनुसार 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है द्यचुनाव के वक्त चुनाव आयोग खासकर यह दिशा निर्देश सभी राजनीतिक पार्टियों को देती है कि वह अपने उम्मीदवारों को यह सख्त हिदायत दें कि वह चुनाव प्रचार में ऐसी कोई बात जनता के सामने उनके भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं करेंगे अगर वह ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और उन पर जनप्रतिनिधि अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो अपराध के लिए धाराएं हैं उनके अनुसार उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें दोषी पाए जाने पर दंड का भागीदार भी बनना पड़ेगा।

☆ दहेज देने या लेने के लिए या दहेज के लिए प्रताड़ित करने की अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है?

यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होने के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुषप्रेरित करेगा तो उसे 5 वर्षों तक की सजा और कम से कम 15,000/- रुपये तक का जुर्माना या ऐसे दहेज के मूल्य तक की राशि इनमें से जो भी अधिक हो की सजा दी जा सकती है इसकी व्यवस्था दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में किया गया है साथ ही अगर कोई व्यक्ति दहेज के लिए या किसी अन्य बातों के लिए अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है या क्रूरता करता है तो इसके लिए दंड की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 में किया गया है जिसके तहत दोषी व्यक्ति को 3 वर्षों तक के लिए कारावास और जुर्माना हो सकता है यह एक संगेय अपराध माना जाता है साथ ही यह अजमानतीय भी होता है, इसका विचारण फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट करते हैं।

☆ क्या किसी मुकदमे को लड़ने से वकील मना कर सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता समुदाय को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि वकील या उनके संगठन किसी अभियुक्त की ओर से न्यायालय में पेश होने से इंकार नहीं कर सकते हैं भले ही वह आतंकी बलात्कारी हत्यारा या कोई अन्य क्यों ना हो ,इस तरह का कोई भी इनकार संविधान का बार काउंसिल के मानकों का और भगवत गीता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने अपने एक आदेश में इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि देशभर में बार एसोसिएशन और वकीलों द्वारा किसी न किसी कारण से अभियुक्तों की ओर से न्यायालय में पेश नहीं होने का चलन बढ़ रहा है। न्यायमूर्ति कि उक्त खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेशेवर आचार नीति की मांग है कि यदि मुदालय फीस देने को तैयार है तो वकील बहस करने से इनकार नहीं कर सकता है इसलिए बार एसोसिएशन का इस तरह का प्रस्ताव कि उनका कोई भी साथी किसी खास अभियुक्त के मामले में न्यायालय में पेश नहीं होगा संविधान कानून और पेशेवर आचार नीति के सभी मानदंडों के विरुद्ध तथा बार एसोसिएशन की महान परंपरा के भी विरुद्ध है जो हमेशा किसी अपराध के लिए अपराधी का बचाव करने के लिए तत्पर रहती है ।वर्ष 2007 में एक आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों और कोयंबटूर के वकीलों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दार आपराधिक मामलों को खारिज करते हुए खंडपीठ ने उपर्युक्त निर्णय दिया था।

☆ क्या पुलिस किसी अपराधी की गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी का विरोध करने पर उसकी हत्या भी कर सकती है?

यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43(4) से यह स्पष्ट होता है कि यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उसकी मृत्यु कारित कर सकता है या अगर खतरनाक अपराधी जिस पर हत्या का आरोप हो वह कैद से फरार हो रहा हो तो उसकी हत्या पुलिस कर सकती है या सेल्फ डिफेंस में भी पुलिस वैसे मुदालय की हत्या कर सकती है। पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर के मामले भी काफी चर्चा में इन दिनों रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में कई फर्जी एनकाउंटर की बातें मीडिया में सुनने को मिली है जब भी कोई एनकाउंटर का विरोध होता है तो सरकार उसे सीबीआई के हवाले जांच करने के लिए भेज देती है ताकि उनके सरकार की फजीहत ना हो।

शुद्ध चावल एवं मक्के के आटे से निर्मित नमकीन

Dhunky
NAMKEEN

Shree Shyamji Udyog

गजब स्वाद की ! गजब कहानी !

fssai

Lic No. 10424110000004

Veg Biryani
masala pola
katori chaat
rings
snacks

Expanding our Namkeen family!
Dealers inquiries welcome, contact us today!

NEAR JAI PRAKASH EVENING INTER COLLEGE
JANDAHA ROAD HAJIPUR (VAISHALI)
MOB: 7782053204

MADE IN INDIA

PURE

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008